लखनऊ

बुधवार, 19 अगस्त , 2026

वर्ष : 11 । अंक: 350

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, वह कभी असफल नहीं होता।

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi | NIGHT 28° Low

संक्षेप

डिप्टी सीएम शिंदे के कार्यक्रम में बड़ी चूक, 'वंदे मातरम' की जगह बजा दिया लता मंगेशकर का गाना, 4 मिनट तक खड़े रहे लोग

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में आयोजित एक हाई-प्रोफाइल सरकारी कार्यक्रम में उस वक्त बेहद असहज स्थिति पैदा हो गई, जब आधिकारिक 'वंदे मातरम' की जगह कोई और ही गाना बजने लगा। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह रही कि मंच पर खुद सूबे के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद थे। इस भारी चूक के कारण पूरी सभा करीब चार मिनट तक मौन खड़ी रही। इस अजीबोगरीब घटना ने आयोजनकर्ताओं की बड़ी लापरवाही को उजागर कर दिया है, जिसके बाद खुद शिंदे को माइक संभालकर इस फजीहत के लिए माफी मांगनी पड़ी। दरअसल, ठाणे में आयोजित इस अहम सरकारी कार्यक्रम में जब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मंच पर पहुंचे, तो प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम की शुरुआत में 'वंदे मातरम' के गायन की घोषणा की गई। सम्मान में वहां मौजूद सभी लोग अपनी जगह पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए, लेकिन तभी स्पीकर पर आधिकारिक गीत की जगह स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के एक पुराने प्राइवेट एलबम का गाना बजने लगा। हालांकि इस गीत के बोल भी 'वंदे मातरम'ही थे, लेकिन यह वह वास्तविक स्वरूप नहीं था जिसे सरकारी आयोजनों में बजाया जाना अनिवार्य है। गलत गीत बजने के बावजूद सम्मान की खातिर पूरी सभा और मंच पर मौजूद तमाम नेता करीब चार मिनट तक शांति से खड़े रहे। डिप्टी सीएम शिंदे के हाव-भाव से साफ झलक रहा था कि उन्हें भी इस चूक का तुरंत अहसास हो गया था। गाना खत्म होने के बाद जब शिंदे ने लोगों को संबोधित करना शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले इस गलती के लिए खुले मंच से खेद जताया।

मोदी जी, हमारे MLA कुलदीप कुमार कहाँ हैं? केजरीवाल ने पूछा - यह कैसी गुंडागर्दी है दिल्ली में?

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में एक सफाई कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या किए जाने के बाद हुए बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शनों के मद्देनजर, NH-24 पर खिचड़ीपुर बस स्टैंड के पास दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए। इस घटना के बाद स्थानीय सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किए और न्याय, दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी तथा पीड़ित परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग की। मामला तब राजनीतिक टकराव में बदल गया जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक कुलदीप कुमार को पुलिस ने तब हिरासत में ले लिया, जब वे पीड़ित परिवार का पक्ष रख रहे थे। ANI से बात करते हुए, AAP विधायक संजीव झा ने राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति की आलोचना की और कहा कि खुलेआम हत्याएं हो रही हैं। फिर भी पुलिस कुछ नहीं करती, जबकि जो लोग आवाज़ उठाते हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है? दिल्ली देश की राजधानी है... जब तक हमें कुलदीप कुमार के बारे में पता नहीं चल जाता, हम यहां से नहीं हटेंगे। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि हिरासत में लिए जाने के बाद अधिकारी विधायक के ठिकाने के बारे में जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं।

'गुलाम कश्मीर में दमन बंद करे पाकिस्तान, दुनिया दिखाए एकजुटता'

पाक सुरक्षा बलों की बर्बरता पर भारत का कड़ा रुख

नई दिल्ली, एजेंसी। पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में पिछले कुछ महीनों से चल रहे जन आंदोलन के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वहां की जनता को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ज्यादती के कारण कई लोगों की जानें गई हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। साथ ही रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं।

जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, "वहां रोजमर्रा की आम जरूरतों वाली आवश्यक वस्तुओं पर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। हालात ऐसे हैं कि वहां के लोगों को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है और उन्हें यह मिलनी चाहिए।" विदेश मंत्रालय ने पिछले कुछ महीनों में भी बार-बार पीओके की स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जायसवाल ने पिछले दिनों कहा था कि जून से अब तक 90 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं।

जनता के असंतोष का जवाब गोलियों, बिजली-पानी की कटौती, डराने-धमकाने और दमन से दिया गया। तथाकथित स्थानीय चुनावों को भी भारत ने "पूरी तरह से दिखावा" बताते हुए कहा था कि, 'ये हकीकत को छिपाने का प्रयास हैं।' भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील कर चुका है कि पाकिस्तान को उसके अत्याचारों और मानवाधिकार उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।

पिछले कुछ हफ्तों से जम्मू-कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। वहां की जनता लगातार पाकिस्तान सरकार और पाक सेना के खिलाफ आंदोलन कर रही है। महंगाई, बिजली के ऊंचे बिल, बुनियादी सुविधाओं की कमी और राजनीतिक अधिकारों की मांग को लेकर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। आंदोलनकारियों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान सेना और सुरक्षा बलों ने आंदोलनकारियों पर बर्बर कार्रवाई की है। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। रावलकोट, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और कोटली जैसे इलाकों में लंबे मार्च और रैलियों पर घातक बल का इस्तेमाल किया गया।

यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने का रास्ता साफ, राष्ट्रपति से मिली बिल को मंजूरी

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2026 और भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन से जुड़े कानून को मंजूरी दे दी है। इन विधेयकों को संसद ने 10 अगस्त को पारित किया था।

भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन से सरकार को यूपीआइ और रुपे कार्ड लेनदेन पर शुल्क लगाने का कानूनी आधार मिल गया है। सरकार अधिसूचना के जरिये यह तय कर सकेगी कि किन इलेक्ट्रानिक भुगतान माध्यमों या लेनदेन पर 'व्यवसायी रियायती दर' (एमडीआर) शुल्क नहीं लगेगा।

फिलहाल बैंक और भुगतान प्रणाली प्रदाता यूपीआइ और रुपे डेबिट कार्ड से किए गए भुगतान पर यूजर से शुल्क नहीं ले सकते हैं। एनपीसीआइ की अध्यक्षता वाली यूपीआई एवं सेवा संचालन समिति अब एमडीआर शुल्क के संबंध में निर्णय लेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन में कहा था कि यूजर के लिए यूपीआई भुगतान निःशुल्क बना रहेगा और भविष्य में एमडीआर शुल्क कुछ निश्चित श्रेणियों के कारोबारी लेनदेन पर ही लागू होगा। वहीं, कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम का उद्देश्य विदेशी पूंजी आकर्षित करना, घरेलू इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देना और विदेशी क्लाउड कंपनियों के लिए भारतीय डेटा केंद्रों का इस्तेमाल सुगम बनाना है।

स्कूल ठीक करो अभियान : अभिजीत दीपके का हिंगोली में प्रदर्शन

मुंबई, एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत महाराष्ट्र के हिंगोली में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। सीजेपी का ये आंदोलन राज्य के ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं और व्यवस्था सुधारने को लेकर किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके ने हिंगोली के प्राथमिक स्कूल के प्रधानाचार्य पर कई गंभीर आरोप लगाए।

अभिजीत दीपके ने कहा, "यहां के प्रधानाचार्य नशे की हालत में स्कूल में आते थे। हम प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मुझे जानकारी मिली है कि प्रिंसिपल को उनके पद से हटा दिया गया है। हम दो और शिक्षकों की भर्ती की भी मांग कर रहे हैं। यहां के ग्रामीण तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है।"

अपने पैतृक गांव से की थी अभियान की शुरुआत

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के गांवों में सरकारी स्कूलों के हालात पर सवाल उठाए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों पर इन स्कूलों की अनदेखी का आरोप लगाया है। अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के हिंगोली में अपने पैतृक गांव से 'स्कूल ठीक करो' अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में कोई भी पार्टी रही हो, सरकारी स्कूलों की अनदेखी होती रही है। दीपके ने कहा कि बच्चों को समान अवसर नहीं मिल रहा है और गांवों के स्कूलों की हालत सुधारने के लिए अब सवाल पूछने होंगे। उन्होंने निजी स्कूलों में फीस तय करने की भी मांग की।

सोशल मीडिया पर सेंसरशिप, 5 महीने में ब्लॉक किए 1.95 लाख अकाउंट... खरगे ने सरकार को घेरा

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार (18 अगस्त) को मोदी सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला किया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने मार्च और जुलाई 2026 के बीच सोशल मीडिया कंपनियों को 1.95 लाख ब्लॉकिंग आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर भारतीय के बोलने, सवाल करने और असहमति जताने के लोकतांत्रिक अधिकार पर सुनियोजित हमला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की सोशल मीडिया रोक लगाने की कार्रवाई उतनी ही निंदनीय है, जितना युवाओं पर किया गया लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल करना है। खरगे ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा 'मोदी सरकार ने बोलने, सवाल करने और असहमति व्यक्त करने के प्रत्येक भारतीय के लोकतांत्रिक अधिकार पर अपना सबसे दुस्साहसी और सुनियोजित हमला किया है। सोशल मीडिया पर उसकी सेंसरशिप उतनी ही निंदनीय है जितनी कि हमारे युवाओं पर लाठीचार्ज और पेलेट गन का इस्तेमाल!'।

समर्थकों पर ऑनलाइन उत्पीड़न का आरोप

इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों पर ऑनलाइन उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं की निजी जानकारी सार्वजनिक की जा रही है और उन्हें बलात्कार की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा 'आजकल इस सरकार की आलोचना करने वाला कोई भी रचनाकार, पत्रकार या आम नागरिक, तुरंत हटाए जाने, धमकी भरे एफआईआर नोटिस और सुनियोजित धमकियों का सामना करता है। वहीं दूसरी ओर, सत्ताधारी पार्टी के अंधभक्त बेखौफ होकर महिलाओं की निजी जानकारी लीक करते हैं, बलात्कार की धमकियां देते हैं और संगठित उत्पीड़न अभियान चलाते हैं।

'5 महीनों में करीब 1.95 लाख ब्लॉकिंग आदेश'

खरगे के मुताबिक, केंद्र सरकार ने पांच महीनों में करीब 1.95 लाख ब्लॉकिंग आदेश जारी किए गए। उन्होंने कहा 'आज हम जो देख रहे हैं वह तो बस हिमबर्ग का एक छोटा सा हिस्सा है। महज 5 महीनों में 1.95 लाख ब्लॉकिंग ऑर्डर। हर 68 सेकंड में एक। ये अपराधियों के खिलाफ नहीं, बल्कि छात्रों, उन युवा भारतीयों के खिलाफ हैं जो अपने भविष्य और धांधली वाली परीक्षाओं के लिए जवाबदेही की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे थे।

TRE-4 नोटिफिकेशन में देरी पर Bihar सरकार को अल्टीमेटम

नई दिल्ली, एजेंसी। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) के चौथे चरण को समय पर आयोजित करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को मांग की कि परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन 24 घंटे के भीतर जारी किया जाए, वरना वे इस्तीफे की मांग को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव कर सकते हैं। कई रिसर्च स्कॉलर और नौकरी के उम्मीदवार पटना के गर्दनीबाग इलाके में कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के नए नियम और राज्य सिविल सेवा परीक्षा में विसंगतियां शामिल हैं। इसके अलावा, वे BPSC-TRE 4 में एक ही चरण की परीक्षा, गलत तरीकों से नौकरी पाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, BSSC भर्तियों में पारदर्शिता और परीक्षा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं।

आईएसआई के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, आतंकी मोहम्मद जफर गिरफ्तार

14 राज्यों से दबोचे गए 200 से अधिक ऑपरेटिव्स

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

मेरठ। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और खूंखार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। यूपी एटीएस ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक अहम आतंकी मोहम्मद जफर को गिरफ्तार कर उसके खतरनाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इस बड़ी कामयाबी के बाद खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 'एक्स' पर पोस्ट कर मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति की सराहना की और सुरक्षाबलों के इस सफल ऑपरेशन की जानकारी दी।

गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी पोस्ट में स्पष्ट किया कि मोदी सरकार ने आईएसआई का सहयोग करने वाले पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि भारतीय सुरक्षाबलों ने 14 राज्यों में एक साथ सघन अभियान चलाते हुए 200 से अधिक स्लीपर सेल और ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया है, जिससे देश पर होने वाले खतरनाक हमलों की साजिश नाकाम हो गई। अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश (वेस्ट यूपी) में अब तक शहजाद भट्टी और सरफराज डोगरा के गिरोह से जुड़े 16 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा जा चुका है।

किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर निशाना, बोले- PM Modi के दिमागी नक्सल बयान से घबराई पार्टी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कांग्रेस पर माओवादी पार्टी में बदलने का आरोप लगाया। यह आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में दिमागी नक्सलियों के जिक्र को लेकर मचे राजनीतिक विवाद के बीच लगाया गया। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि हालांकि जंगलों में सक्रिय हथियारबंद नक्सलियों को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है, लेकिन देश के अलग-अलग हिस्सों में दिमागी नक्सली अभी भी मौजूद हैं और उन्हें पहचानकर अलग-थलग करने की ज़रूरत है। इन बयानों की विपक्ष के नेताओं ने आलोचना की; कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने 'X' पर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है।

भाजपा संगठन में बड़ा फेरबदल, विनोद तावड़े यूपी के प्रभारी नियुक्त

नई दिल्ली, एजेंसी। बीजेपी ने पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के चुनावों के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति की है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की अगुवाई में घोषित नई राष्ट्रीय टीम में कई नए चेहरों को जगह दी गई है, जबकि चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी अनुभवी नेताओं को सौंपी गई है।

पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया है। उनके साथ जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, ऐसे में चुनाव की कमान तावड़े को सौंपे जाने को अहम माना जा रहा है।

पंजाब विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश पुनिया को दी गई है। पंजाब में बीजेपी के सामने संगठन को मजबूत करने और अपने चुनावी आधार का विस्तार करने की चुनौती है। वहीं, राज्यसभा सांसद तरुण चुग को गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया है। चुग पहले भी पार्टी संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं।

बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। वहीं, पूर्व आरएसएस नेता राम माधव और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

ई 20 पेट्रोल के खिलाफ जंतर-मंतर पर होगा बड़ा प्रदर्शन, तहसीन पूनावाला ने किया भूख हड़ताल का ऐलान

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में ई20 पेट्रोल को लेकर चल रही बहस अब सड़कों पर भी तेज होती नजर आ रही है। ई20 के खिलाफ आवाज उठा रहे तहसीन पूनावाला ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर दो दिवसीय विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी जानकारी दी। उनके मुताबिक, टीम भारत की ओर से 22 और 23 अगस्त को जंतर-मंतर पर 'जनता दरबार' आयोजित किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की गई है।

पूनावाला के अनुसार, 22 अगस्त को सुबह 11 बजे जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन शुरू होगा, जो आगे भी जारी रहेगा। इसके बाद 23 अगस्त को सुबह 11 बजे से प्रदर्शन के साथ भूख हड़ताल की जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि दोनों दिन 5,000 से अधिक लोग प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं और प्रदर्शनकारियों की संख्या 10,000 तक पहुंचने की संभावना है।

प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में ई10 पेट्रोल को लेकर स्पष्ट व्यवस्था करना शामिल है। पूनावाला का कहना है कि पुराने ऐसे वाहनों, जिन्हें ई20 ईंधन के अनुरूप तैयार नहीं किया गया है, उनके लिए ई10 पेट्रोल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उनका दावा है कि पुराने वाहनों में ई20 के इस्तेमाल से माइलेज में कमी आने के साथ-साथ कुछ वाहन कंपोनेंट पर भी असर पड़ सकता है। पूनावाला ने ई0 पेट्रोल की कीमत कम करने की भी मांग की है। इसके अलावा ई20 से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी सार्वजनिक करने की मांग उठाई गई है। उनका कहना है कि ईंधन नीति से जुड़े दस्तावेज आम लोगों के सामने आने चाहिए, ताकि ई20 को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सके।

ई20 विरोधी प्रदर्शन की प्रमुख मांगों में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पद से हटाने की मांग भी शामिल है। पूनावाला की ओर से जारी मांगों में इसे स्पष्ट तौर पर शामिल किया गया है। उन्होंने अपने संदेश के अंत में 'चॉइस नहीं तो वोट नहीं' का नारा भी दिया है। इससे संकेत मिलता है कि ई20 को लेकर लोगों को विकल्प नहीं मिलने की स्थिति में इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा सकती है।

सत्ता बदलते ही केस वापस लेने के खेल पर लगी रोक

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय चुनावी राजनीति में काले धन और अनुचित साधनों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद कड़ा फैसला सुनाया है। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के दौरान गड़बड़ी या काले धन के इस्तेमाल के आरोपी नेताओं पर सरकार बदलते ही राजनीतिक रसूख के चलते दर्ज मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं। इस मनमानी पर कड़ा प्रहार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अब चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए संबंधित उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ ने मौजूदा सांसदों और विधायकों से जुड़े पुराने नियम का हवाला देते हुए यह बड़ा आदेश दिया। पीठ ने कहा कि जिस तरह मौजूदा सांसदों और विधायकों के मुकदमे केवल हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद ही वापस हो सकते हैं, ठीक वही नियम अब चुनाव लड़ने वाले सामान्य उम्मीदवारों पर भी समान रूप से लागू होगा। अदालत ने टिप्पणी की कि यह कदम चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता लाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इससे संभावित उम्मीदवारों को कड़ा संदेश जाएगा कि गलत काम करके कोई भी नेता सिर्फ सत्ता परिवर्तन के दम पर बच नहीं सकता। अदालत ने राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद मुकदमों को वापस लेने की परिपाटी पर गंभीर चिंता जताई। पीठ ने कहा कि यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि राजनीतिक बदलाव के बाद अक्सर ऐसे अनुचित फैसले लिए जाते हैं।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: एसआईटी जांच में चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट, टीम ने शासन को सौंपी रिपोर्ट

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने अपनी फाइनल रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। गृह विभाग ने रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को उपलब्ध करा दिया है। सूत्रों के मुताबिक, फाइनल रिपोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को क्लीन चिट दी गई है। वहीं, ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्र पर भी कोई आरोप तय नहीं किए जाने की बात सामने आ रही है।

ट्रस्ट के अनुरोध पर शासन ने 13 जून को लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी गठित की थी। आईजी रेंज किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार को एसआईटी का सदस्य बनाया गया था। टीम ने जांच के दौरान चढ़ावे से जुड़े मामले में सामने आए तथ्यों, दस्तावेजों और संबंधित लोगों के बयानों की पड़ताल की।

आठ आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा

एसआईटी ने 23 जून को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। प्रारंभिक रिपोर्ट में मामले में कड़ी कार्रवाई की संस्तुति की गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को राम जन्मभूमि थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की शिकायत पर दर्ज मुकदमे में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू को नामजद किया गया था। इसके अलावा अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ही आरोपियों की गिरफ्तारी समेत अन्य कार्रवाई की गई थी।

चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका पर उठे थे सवाल

चढ़ावे की रकम में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे। विवाद के बीच दोनों ने ट्रस्ट में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। अब प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT की रिपोर्ट में दोनों के नाम नहीं होने से उन्हें राहत मिली है।

आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 98 लीटर कच्ची शराब बरामद

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। आबकारी आयुक्त के निर्देश पर चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के तहत मंगलवार को सुल्तानपुर में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया। जिलाधिकारी सुल्तानपुर एवं उप आबकारी आयुक्त अयोध्या प्रभार के निर्देश तथा जिला आबकारी अधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई।

आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 रण विजय सिंह और क्षेत्र-4 अरुण कुमार ने टीम के साथ कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के ग्राम चुनहा में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान टीम ने करीब 98 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। मौके से करीब 1220 किलोग्राम लहन नष्ट कराया गया। मामले में आबकारी अधिनियम की धारा 60(1) के तहत तीन अभियोग पंजीकृत किए गए। अभियान के दौरान क्षेत्र में संचालित आबकारी दुकानों का भी निरीक्षण किया गया। दुकानों में उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने के साथ ही गुप्त रूप से टेस्ट परचेज भी कराया गया। इसके अलावा कबाड़ की दुकानों और ईंट-भट्ठों की भी गहनता से जांच की गई। आबकारी विभाग की टीम ने ग्रामीणों को अवैध शराब के सेवन से होने वाले नुकसान और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरों के प्रति जागरूक भी किया। अधिकारियों ने अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही।

भाई ने कहा– पढ़ाई छोड़ो, पर्दे में रहो और हलाला करो... बरेली में LLB छात्रा ने अपने घर वालों पर लगाए संगीन आरोप

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जतनगर क्षेत्र में एलएलबी की पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने अपने ही भाइयों, भाभियों और रिश्तेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का आरोप है कि परिवार के लोग उस पर पढ़ाई छोड़ने और घर की महिलाओं की तरह पर्दे में रहने का दबाव बना रहे हैं। आरोप है कि उसके पूर्व पति के साथ हलाला करने के लिए भी दबाव बनाया गया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। पीड़िता की तहरीर पर इज्जतनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता इज्जतनगर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। उसने पुलिस को बताया कि वह एलएलबी की पढ़ाई कर रही है। इसके साथ ही प्रशिक्षु वकील के तौर पर प्रैक्टिस भी कर रही है। उसका कहना है कि वह अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन परिवार के कुछ लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। पीड़िता का आरोप है उसका एक छोटा भाई सऊदी अरब में रहकर मजदूरी करता है और अपनी मां के खर्च के लिए रुपये भेजता है। वहीं उसके दो अन्य भाई और उनकी पत्नियां उसे और उसकी मां को मकान से बाहर निकालने का दबाव बना रहे हैं। इसी बात को लेकर परिवार में पहले भी विवाद हो चुका है।

महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि सात अगस्त को उसके भाई, भाभियां और रिश्ते के मामा समेत कुछ लोग उसके साथ विवाद करने लगे। आरोप है कि इसी दौरान उस पर पूर्व पति के साथ हलाला करने का दबाव बनाया गया। महिला ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उसका पूर्व पति से तलाक हो चुका है और वह इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएगी।

महिला के मुताबिक उसके इनकार करने पर परिवार के लोग नाराज हो गए। आरोप है कि सभी ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। लात-घूंसों से पीटने के साथ उसे धमकाया भी गया। पीड़िता का आरोप है कि परिवार के लोगों ने उससे कहा कि उनके परिवार की महिलाएं पर्दे में रहती हैं और उसे भी उसी तरह रहना होगा।

पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप

आरोप है कि इसी दौरान उससे साफ तौर पर कहा गया कि वह एलएलबी की पढ़ाई छोड़ दे और वकालत की प्रैक्टिस भी बंद कर दे। महिला ने पुलिस को बताया कि वह पढ़ाई जारी रखना चाहती है, लेकिन परिवार के लोग लगातार उस पर दबाव बना रहे हैं। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके और उसकी मां के साथ पहले भी मारपीट की जा चुकी है। परिवार में विवाद बढ़ने के बाद उसने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। मामले की जानकारी मिलने के बाद इज्जतनगर पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस अब आरोपों की जांच कर रही है और घटना से जुड़े लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। वही एएसपी शिवम आशुतोष सिंह ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।

इंजीनियर हत्याकांड में 22 को दर्ज होगा आरोपियो का बयान

सुल्तानपुर। जल निगम के इंजीनियर संतोष कुमार हत्याकांड में आरोपियो का बयान दर्ज करने के लिए सोमवार की तारीख नियत रही। फिलहाल आरोपियो का बयान नहीं दर्ज हो सका। विशेष लोक अभियोजक सुशील उपाध्याय ने बताया कि स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट राकेश पाण्डेय की अदालत ने मामले में आरोपियो का बयान दर्ज करने के लिए 22 अगस्त की तारीख तय किया है। कोतवाली नगर के विनोवापुरी मोहल्ले में किराए के मकान में रहने वाले अधिशासी अभियंता संतोष कुमार की 17 अगस्त साल 2024 को हत्या कर दी गई थी। मामले में जल निगम के सहायक अभियंता अमित कुमार शाह व सह आरोपी प्रदीप राम के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है,जिनके खिलाफ स्पेशल कोर्ट में विचारण चल रहा है। इस मामले को मिशन कनविक्शन के तहत चिन्हित किया गया है।

सलीम निकला भगवान सिंह! आगरा में शिकारी के पास मिली 10 तेंदुओं की खाल, नाम बदलने की क्या थी वजह?

आर्यावर्त संवाददाता

आगरा। आगरा में 10 तेंदुओं की खाल और प्रतिबंधित शिकार उपकरणों के साथ बीते दिनों पुलिस ने एक शिकारी को अरेस्ट किया था। शुरू में इसने अपना नाम सलीम बताया था। लेकिन पुलिस की जांच में आरोपी का नाम भगवान सिंह पता चला है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कथित फर्जी पहचान किसने तैयार की, उसे किस आधार पर उपलब्ध कराया गया और इसका इस्तेमाल वन्यजीव तस्करी से जुड़े नेटवर्क में कैसे किया गया।

अधिकारियों का आरोप है कि इस पहचान का इस्तेमाल किसी कार्रवाई की स्थिति में मामले को सांप्रदायिक रंग देने और जांच की दिशा प्रभावित करने के लिए किया जा सकता था। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पहचान को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और इसके स्रोत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

मामले में Wildlife SOS का नाम सामने आने के बाद जांच का दायरा बढ़ गया है। मध्य प्रदेश की प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ। समिता राजोरा के अनुसार, आरोपी के कथित कबूलनामे और डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां संस्था की कथित भूमिका और उसके कुछ लोगों के संपर्कों की भी पड़ताल कर रही हैं। जांच अब संगठन के सह-संस्थापक और CEO कार्तिक सत्यनारायण तक पहुंच चुकी है। वन विभाग और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) की ओर से उन्हें पूछताछ के लिए समन जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है।

तीन अहम सवालों पर जांच

जांच अधिकारियों के सामने फिलहाल तीन प्रमुख सवाल हैं। पहला, भगवान सिंह को सलीम नाम की कथित पहचान किसने उपलब्ध कराई। दूसरा, इस पहचान का इस्तेमाल वन्यजीव तस्करी से जुड़े किन मामलों या सौदों में किया गया। तीसरा, क्या इस कथित पहचान के जरिए कानूनी कार्रवाई से बचने की कोई व्यवस्था तैयार की गई थी। इसके साथ ही जांच एजेंसियां आरोपी के मोबाइल फोन, डिजिटल रिकॉर्ड और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) की भी जांच कर रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश वन विभाग और WCCB की टीमें मामले से जुड़े संपर्कों और संभावित नेटवर्क की जानकारी जुटा रही हैं। दूसरी ओर, Wildlife SOS ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। संगठन का कहना है कि वह देशभर में वन्यजीवों के बचाव और पुनर्वास के लिए पारदर्शी तरीके से काम करता है।

CEO कार्तिक सत्यनारायण ने कहा कि संगठन के प्रत्येक इंटेलिजेंस ऑपरेशन का आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि वैध एंटी-पोचिंग अभियानों को अपराध के तौर पर पेश किया गया तो इससे वन्यजीव अपराधों की सूचना देने वाले मुखबिरों का मनोबल प्रभावित हो सकता है। संगठन ने जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करने की बात कही है।

10 तेंदुओं की खाल बरामद

मामले में आरोपी भगवान सिंह के पास से 10 तेंदुओं की खाल और कथित अवैध शिकार में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। अब जांच एजेंसियां बरामदगी के साथ-साथ आरोपी की पहचान, उसके संपर्कों और कथित वन्यजीव तस्करी नेटवर्क के बीच संबंधों की पड़ताल कर रही हैं। फिलहाल डिजिटल साक्ष्यों और अन्य रिकॉर्ड के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

पति की बेइंतहा मोहब्बत का दर्दनाक अंत, पत्नी से हॉट टॉक के बाद कमरे में मिली लाश, भाई को फोन कर बोला 'आई लव यू...'

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कटघर थाना क्षेत्र के कमला नगर पीतल बस्ती में 35 वर्षीय रितेश शर्मा का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। पुलिस के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि घटना से कुछ घंटे पहले रितेश का अपनी पत्नी शकुंतला से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद पत्नी घर से बाहर चली गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मूल रूप से संभल जिले के हजरतनगर गढ़ी निवासी रितेश शर्मा अपनी पत्नी शकुंतला के साथ कमला नगर पीतल बस्ती में मकान मालकिन पुष्पा के घर किराए पर रहता था। बताया गया है कि रितेश पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (MR) के तौर पर काम करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसके पास रोजगार नहीं था। काम छूटने के कारण परिवार आर्थिक परेशानी से गुजर रहा था।

परिजनों और आसपास के लोगों के मुताबिक, बेरोजगारी के चलते रितेश मानसिक दबाव में था। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे किसी बात को लेकर उसका पत्नी से विवाद हो गया। कहासुनी बढ़ने के बाद शकुंतला घर से बाहर चली गई। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पत्नी के घर से निकलने के बाद रितेश कमरे में अकेला रह गया। इसी दौरान उसने नए मुरादाबाद इलाके में रहने वाले अपने भाई अनुज को फोन किया। अनुज के मुताबिक, रितेश ने फोन पर सिर्फ आई लव यू कहा और इसके बाद कॉल काट दिया। भाई को उस समय बातचीत का मतलब समझ नहीं आया। कुछ घंटे बाद जब रितेश के बारे में जानकारी मिली तो परिवार में हड़कंप मच गया। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

खिड़की से शव देखकर मकान मालकिन के उड़े होश

शाम करीब पांच बजे मकान मालकिन पुष्पा ऊपर कमरे की तरफ गईं। कमरे के अंदर कुछ असामान्य नजर आने पर उन्होंने खिड़की से झांककर देखा। रितेश का शव फंदे से लटका देखकर वह घबरा गईं और उनकी चीख निकल गई। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे की जांच की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना मिलते ही कटघर थाना प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र सिंह पुलिस टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने रितेश के मोबाइल फोन समेत अन्य पहलुओं की भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, मौत की वास्तविक वजह और घटनाक्रम की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा जांच के बाद ही हो सकेगी। मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे शव का पोस्टमार्टम कराया जाना है। परिवार के लोग भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचेंगे।

पत्नी की तलाश में जुटी पुलिस

घटना के बाद से रितेश की पत्नी शकुंतला का पता नहीं चल पाया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पत्नी के मिलने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी, जिससे विवाद से पहले और बाद की परिस्थितियों की जानकारी मिल सके। फिलहाल पुलिस मामले को हर पहलू से जांच रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस कार्यालय के सामने गूंजा वंदे मातरम, भाजपा ने निकाला जनाक्रोश मशाल जुलूस

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। कांग्रेस मुख्यालय पर सोनिया गांधी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा वंदे मातरम् के कथित अपमान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार देर शाम भाजपा जिला उपाध्यक्ष चंदन नारायण सिंह के नेतृत्व में विशाल जनाक्रोश मशाल जुलूस निकाला। जुलूस में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं राष्ट्रप्रेमी नागरिकों ने सहभागिता की। मशाल जुलूस तिकोनिया पार्क से प्रारंभ होकर डाकखाना चौराहा होते हुए कांग्रेस जिला कार्यालय के सामने पहुंचा। कार्यकर्ताओं के हाथों में तिरंगा और मशालें थीं। पूरे मार्ग में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से वातावरण गूंजता रहा। कांग्रेस जिला कार्यालय के सामने पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का गायन कर राष्ट्रगीत के सम्मान का संदेश दियज्ञं भाजपा जिला उपाध्यक्ष चंदन नारायण सिंह ने कहा पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिला कार्यालय के सामने सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत का गायन करके यह संदेश देने का प्रयास किया है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान किस प्रकार किया जाता है।राजनीति अपनी जगह है,लेकिन राष्ट्र और राष्ट्र के गौरव से जुड़े प्रतीकों का सम्मान सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता राष्ट्र की एकता, अखंडता, स्वाभिमान और सम्मान के लिए सदैव लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाते रहेंगे। मीडिया प्रमुख विजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि जनाक्रोश मशाल जुलूस में जिला उपाध्यक्ष आनन्द द्विवेदी, डॉ. प्रीति प्रकाश, रामेंद्र सिंह राणा, आशीष सिंह रानू, अखिलेश जायसवाल, पूजा गुप्ता, दिनेश चौरसिया, प्रदीप मिश्रा, उज्जवल मिश्रा सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता एवं राष्ट्रप्रेमी नागरिक उपस्थित रहे।

रास्ते पर भरा पानी, बाइक से ले जाना पड़ा नवजात का शव, महिला के जनाजे को बदला रास्ता, व्यवस्था पर सवाल

आर्यावर्त संवाददाता

सहारनपुर। सहारनपुर के गंगोह विकासखंड के नया कुंडा बसी गांव में जलभराव ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गांव की गलियों में इतना पानी भरा है कि लोगों को रोजमर्रा के आवागमन के लिए भी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है।

हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नवजात बच्ची की मौत के बाद उसके शव को बाइक पर रखकर कब्रिस्तान तक ले जाना पड़ा। अगले दिन एक महिला की मौत के बाद मुख्य रास्ते पर पानी भरा होने के कारण उसके जनाजे को भी दूसरे रास्ते से ले जाना पड़ा। इस स्थिति को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है।

नवजात बच्ची का शव बाइक से ले जाना पड़ा

गांव निवासी नदीम की चार दिन की बेटी की रविवार को मौत हो गई थी। गांव की गली में पानी भरा होने के कारण जनाजा ले जाना संभव नहीं था। मजबूरी में बच्ची के शव को बाइक पर रखकर कब्रिस्तान तक ले जाया गया। इस घटना ने गांव की बदहाल व्यवस्था की तस्वीर सामने रख दी।

महिला के जनाजे के लिए भी बदलना पड़ा रास्ता

सोमवार को गांव निवासी पोल्ला की पत्नी की मौत हो गई। मुख्य रास्ते पर पानी भरा होने के कारण ग्रामीण जनाजा लेकर सीधे कब्रिस्तान नहीं जा सके। उन्हें दूसरे रास्ते से होकर कब्रिस्तान जाना पड़ा। लगातार दो दिनों में अंतिम संस्कार से जुड़ी ऐसी स्थिति सामने आने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है।

गलियों में तालाब का पानी भी भर रहा

ग्रामीणों के अनुसार, गांव की कई गलियों में घरों से निकलने वाले गंदे पानी के साथ तालाब का पानी भी भर रहा है। जल निकासी के लिए एक पाइप लाइन बिछाकर मोटर की मदद से पानी निकाला जाता है, लेकिन फिलहाल मोटर बंद पड़ी है। ऐसे में गलियों से पानी निकालने की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों को मजबूरी में गंदे पानी से होकर आना-जाना पड़ रहा है।

मस्जिद तक पहुंचने का रास्ता भी पानी में डूबा

सादिक राव, आमिर, शहजाद, तैमूर, आदिल, आलीम और इस्तखार समेत ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। उनका आरोप है कि प्रशासनिक उपेक्षा के कारण लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने के लिए भी साफ रास्ता नहीं बचा है। ग्रामीणों ने गांव में संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका भी जताई है।

मोटर का तार चोरी, अब फिर कराई जाएगी जल निकासी

खंड विकास अधिकारी परवेज आलम ने बताया कि जल निकासी के लिए लगाई गई मोटर का तार चोरी हो गया था। दोबारा तार मंगाकर जल निकासी की व्यवस्था कराई जाएगी। अधिकारियों के इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों को जलभराव की समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।

सफाई के टेंडर पर सवाल, एसडीएम की फटकार से मंडी में मचा हड़कंप

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। भारतीय सब्जी-फल मंडी अमहट में सफाई और अव्यवस्थाओं को लेकर व्यापारियों का गुस्सा आखिरकार प्रशासन के दरवाजे तक पहुंच गया। शिकायतों की झड़ी के बाद उप जिलाधिकारी गरिमा सोनकिया ने मंडी सचिव और बड़े बाबू को तलब कर जमकर फटकार लगाई। सफाई व्यवस्था सवालों में होने के बावजूद टेंडर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी सामने आने पर उन्होंने टेंडर निरस्त करने के निर्देश दिए। व्यापारियों का आरोप है कि मंडी में पिछले करीब छह महीने से सफाई का ठेका नहीं हुआ। जब टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई तो कथित तौर पर उसी फर्म को दोबारा ठेका देने की कोशिश की गई, जिसके पिछले कार्यकाल की सफाई व्यवस्था पर व्यापारी पहले से सवाल उठाते रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि जिस फर्म का ठेका समाप्त हो चुका था, उससे भी काम कराए जाने के आरोप हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सफाई व्यवस्था ही बदहाल रही तो आखिर ठेके की 'मेहरबानी' किसके लिए थी? अध्यक्ष मोहम्मद शमीम उर्फ लईया के मुताबिक 10 अगस्त को मंडी निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी ने व्यापारियों की मौजूदगी में टेंडर खुलवाने का निर्देश दिया था। आरोप है कि इसके बावजूद उसी फर्म के पक्ष में कथित तौर पर टेंडर देने का प्रयास किया गया। मामला सामने आने पर एसडीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब मंडी में सफाई नहीं तो भुगतान भी नहीं होगा। साथ ही टेंडर निरस्त करने के निर्देश दिए। व्यापारियों ने मंडी की बदहाली का दूसरा चेहरा भी प्रशासन के सामने रखा। उनका कहना है कि हल्की बारिश में ही परिसर में जलभराव हो जाता है। नालियां चोक हैं, शौचालय जर्जर और बदबूदार हैं तथा पेयजल की समुचित व्यवस्था तक नहीं है। फल-सब्जियों के कारोबार वाली मंडी में पानी भरने से सामान खराब होने और व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होने की शिकायत भी सामने आई। यानी जिस मंडी में सब्जियां बिकनी चाहिए, वहां बारिश होते ही पानी की 'फ्री सप्लाई' शुरू हो जाती है! व्यापारियों ने मंडी लाइसेंस जारी करने के नाम पर निर्धारित शुल्क से कई गुना अधिक रकम वसूले जाने का आरोप भी लगाया। शिकायतों के बाद अब प्रशासन के सामने मंडी की व्यवस्थाओं के साथ-साथ कथित वसूली के आरोपों की भी जांच की चुनौती है। इससे पहले 7 अगस्त को उद्योग बंधु की बैठक में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री रवीन्द्र त्रिपाठी ने जिलाधिकारी के सामने मंडी की समस्याएं उठाई थीं।

रास्ता न दिला पाएं तो लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार सबको सस्पेंड करो: मुख्यमंत्री

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि संबंधी मामलों में लापरवाही और उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान एक महिला ने दबंगों द्वारा रास्ता रोके जाने की शिकायत की। महिला ने मुख्यमंत्री को बताया कि दबंग धमकी देते हैं कि चाहे जहां शिकायत कर लो, वे रास्ता नहीं देंगे। महिला की पीड़ा सुनकर मुख्यमंत्री ने तत्काल अधिकारियों को मामले का निस्तारण कर महिला को रास्ता दिलाने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यदि लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार रास्ता दिलाने में खुद को असमर्थ मानते हैं तो उन सभी को निलंबित किया जाए। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों में यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और मामले की गंभीरता के अनुसार निलंबन की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।सोमवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री करीब 200 लोगों के बीच पहुंचे और एक-एक कर उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री ने लोगों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों को स्वयं अपने हाथ में लेकर उनका अवलोकन किया तथा शिकायतों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक प्रार्थना पत्र का गंभीरता से संज्ञान लेकर उसका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाए।मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में आए लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी समस्या के समाधान के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। शासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र और पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले तथा उसकी समस्या का समाधान पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कराया जाए।जनता दर्शन के दौरान कई अन्य लोगों ने भी भूमि और राजस्व से संबंधित मामलों में राजस्व कर्मियों द्वारा लापरवाही किए जाने की शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने रखीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों की जांच कराई जाए और जहां भी लापरवाही सामने आए, वहां जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भूमि विवादों और जनसमस्याओं के निस्तारण में अनावश्यक देरी या लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जनता की शिकायतों का समाधान केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि मौके पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में वास्तविक रूप से लोगों को रास्ता, कब्जा हटाने, राजस्व अभिलेखों में सुधार या अन्य वैधानिक सहायता की आवश्यकता है, उनमें संबंधित विभाग तत्काल कार्रवाई करें। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए पूरी गंभीरता से काम करें।जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके उपचार में हरसंभव सहायता करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र और जरूरतमंद लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएं, ताकि उन्हें उपचार की सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आयुष्मान योजना के बावजूद किसी जरूरतमंद को इलाज के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी मदद उपलब्ध कराई जाएगी।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को उपचार के लिए आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में आवश्यक औपचारिकताएं तेजी से पूरी कराई जाएं और जरूरतमंदों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जाए।जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री का जोर इस बात पर रहा कि शासन-प्रशासन की योजनाओं और व्यवस्थाओं का वास्तविक लाभ आम नागरिक तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ काम करने तथा शिकायतों का निष्पक्ष और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पीआरडी जवानों को मुख्यमंत्री योगी की बड़ी सौगात, ड्यूटी भत्ता 500 से बढ़ाकर 600 रुपये और हर साल पांच लाख तक मुफ्त इलाज

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों को बड़ी सौगात देते हुए उनके दैनिक ड्यूटी भत्ते में वृद्धि की घोषणा की। अब पीआरडी स्वयंसेवकों को 500 रुपये के स्थान पर प्रतिदिन 600 रुपये ड्यूटी भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पीआरडी जवानों और उनके परिवार के सदस्यों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की भी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीआरडी स्वयंसेवकों ने कानून-व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, यातायात संचालन, चुनाव ड्यूटी और विभिन्न महत्वपूर्ण आयोजनों में पुलिस एवं प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। उनके योगदान और सेवाभाव को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है।योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित पीआरडी जवानों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने स्वयंसेवकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा के कार्ड वितरित कर 'मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना' का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर लखनऊ में करीब 23 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बहुमंजिला पीआरडी बैरक का शिलान्यास भी किया।अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1948 में गठित प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों को वर्ष 2019 तक मात्र 250 रुपये प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता मिलता था। वर्ष 2019 में इसे बढ़ाकर 375 रुपये, वर्ष 2022 में 395 रुपये और वर्ष 2025 में बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन किया गया। अब एक बार फिर इसमें वृद्धि करते हुए ड्यूटी भत्ता 600 रुपये प्रतिदिन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीआरडी के 75 वर्षों के इतिहास में ड्यूटी भत्ता 250 रुपये तक ही पहुंच पाया था, जबकि पिछले आठ वर्षों में यह 250 रुपये से बढ़कर 600 रुपये होने जा रहा है। यह वृद्धि सौ प्रतिशत से भी अधिक है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने और शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में पीआरडी स्वयंसेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पुलिस और प्रशासन के सहयोग में पीआरडी जवान पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले पीआरडी जवानों को नियमित रूप से ड्यूटी नहीं मिलती थी, लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। पीआरडी के महत्व को समझते हुए सरकार ने उनकी भूमिका को व्यापक बनाया है और अब कई अवसरों पर ड्यूटी के लिए जवान कम पड़ जाते हैं।योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्राकृतिक आपदा हो या महाकुंभ, दीपोत्सव, रंगोत्सव, यातायात व्यवस्था हो या चुनाव ड्यूटी, पीआरडी स्वयंसेवकों ने हर जिम्मेदारी को अनुशासन, सेवाभाव और समर्पण के साथ पूरा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पीआरडी जवानों के योगदान को सम्मान देते हुए उनके कल्याण के लिए लगातार कदम उठा रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि पीआरडी स्वयंसेवकों और उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय उनके प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत प्रदेश के 31 हजार से अधिक पीआरडी स्वयंसेवकों को सरकारी तथा सरकार से संबद्ध अस्पतालों में प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। परिवार के सदस्यों को शामिल करने पर इस योजना से 1.55 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इससे पीआरडी जवानों और उनके परिवारों को गंभीर बीमारी की स्थिति में आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी और उन्हें बेहतर उपचार की सुविधा मिल सकेगी।

संक्षेप

यूट्यूब चैनल खरीदने के नाम पर 1.70 लाख रुपये की साइबर ठगी, नाका पुलिस ने पूरी रकम वापस कराई

लखनऊ। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना नाका हिंडोला पुलिस की साइबर टीम ने तत्परता और तकनीकी सूझबूझ का परिचय देते हुए यूट्यूब चैनल खरीदने के नाम पर हुई 1 लाख 70 हजार रुपये की साइबर ठगी की पूरी धनराशि पीड़ित को वापस करा दी। बैंकिंग लेनदेन का तकनीकी विश्लेषण कर पुलिस टीम ने ठगी की रकम को ट्रेस किया और उसे पीड़ित के खाते में वापस कराया।पुलिस उपायुक्त पश्चिमी के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी एवं सहायक पुलिस आयुक्त कैसरबाग के निर्देशन तथा थाना नाका हिंडोला के थानाध्यक्ष विवेक कुमार चौधरी के नेतृत्व में थाना नाका की साइबर टीम द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।इसी क्रम में 6 अगस्त 2026 को नाका हिंडोला क्षेत्र निवासी रवींद्र नाथ शुक्ल ने पुलिस को शिकायत दी कि उनके पोते अयांश शुक्ल के साथ यूट्यूब चैनल खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। साइबर जालसाजों ने पीड़ित के बैंक खाते से 1 लाख 70 हजार रुपये की धनराशि धोखाधड़ी से निकाल ली थी।मामले की जानकारी मिलते ही थाना नाका के साइबर हेल्प डेस्क प्रभारी उपनिरीक्षक सतेन्द्र कुमार सैनी ने तत्परता दिखाते हुए पीड़ित की शिकायत साइबर अपराध पोर्टल पर दर्ज कराई। इसके बाद थाना नाका की साइबर टीम ने बैंकिंग लेनदेन से संबंधित विवरण का गहन तकनीकी विश्लेषण शुरू किया।पुलिस टीम ने साइबर ठगी में इस्तेमाल किए गए बैंकिंग लेनदेन की जानकारी और धनराशि के प्रवाह का विश्लेषण करते हुए 1 लाख 70 हजार रुपये की पूरी रकम को ट्रेस कर लिया। आवश्यक कार्रवाई के बाद पुलिस ने ठगी की पूरी धनराशि पीड़ित को वापस करा दी। रकम वापस मिलने पर पीड़ित ने नाका पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।पुलिस अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर बैंक खाते, ओटीपी, एटीएम कार्ड, यूपीआई या अन्य बैंकिंग संबंधी जानकारी साझा न करें। ऑनलाइन खरीदारी अथवा किसी डिजिटल सेवा के लिए भुगतान करने से पहले संबंधित व्यक्ति या संस्था की विश्वसनीयता की जांच अवश्य करें। साइबर ठगी होने पर बिना देरी किए साइबर अपराध पोर्टल या पुलिस को सूचना दें, जिससे ठगी की धनराशि को समय रहते रोकने और वापस कराने की कार्रवाई की जा सके।साइबर ठगी की धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक सतेन्द्र कुमार सैनी तथा कांस्टेबल प्रभात त्रिपाठी, थाना नाका हिंडोला, लखनऊ शामिल रहे।

राजकीय आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में 40 अनुदेशक पदों पर जल्द होगी भर्ती

लखनऊ। प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने तथा उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। समाज कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित राजकीय आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में अनुदेशकों के रिक्त पदों पर जल्द ही पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं अन्य योग्य लोगों को अनुदेशक के रूप में लगाया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न राजकीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों में कुल 40 अनुदेशक पद रिक्त हैं। इनमें राजकीय गोविंद बल्लभ पंत पॉलिटेक्निक, मोहन रोड, लखनऊ में 7 पद, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), बक्शी का तालाब, लखनऊ में 23 पद, राजकीय आईटीआई/पॉलिटेक्निक, गोरखपुर में 9 पद तथा राजकीय आईटीआई/पॉलिटेक्निक, प्रतापगढ़ में 1 पद रिक्त है।विभाग की ओर से कहा गया है कि रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूरा किया जाएगा। इसके लिए योग्य अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। भर्ती होने के बाद तकनीकी संस्थानों में शिक्षण व्यवस्था को और मजबूत करने के साथ विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों का बेहतर व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध कराया जा सकेगा।समाज कल्याण विभाग ने कहा कि सरकार युवाओं के कौशल विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को रोजगार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

छुट्टा गोवंश के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने 5 अरब रुपये की धनराशि स्वीकृत की

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में छुट्टा और निराश्रित गोवंश के संरक्षण तथा उनके भरण-पोषण के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 5 अरब रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। स्वीकृत धनराशि की पहली किस्त का उपयोग अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, संचालन तथा संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण के लिए किया जाएगा। गोवंश के भरण-पोषण पर अधिकतम 50 रुपये प्रतिदिन प्रति गोवंश की दर से धनराशि खर्च की जा सकेगी।इस संबंध में पशुधन विभाग की ओर से शासनादेश जारी कर निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित और सत्यापित गोवंश के भरण-पोषण के लिए ही किया जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य मद में धनराशि खर्च करना वित्तीय नियमों का उल्लंघन और धनराशि का दुरुपयोग माना जाएगा।शासनादेश के अनुसार धनराशि के आहरण और व्यय के दौरान यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि स्वीकृत बजट का उपयोग केवल पात्र गोवंश के भरण-पोषण पर ही किया जाए। इसके लिए निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को पूरी तरह जिम्मेदार बनाया गया है। विभाग को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिन कार्यों और मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उनके लिए पहले राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत न हुई हो और न ही संबंधित कार्य किसी अन्य योजना या कार्यक्रम में शामिल हो।सरकार की ओर से स्वीकृत धनराशि का आवंटन और हस्तांतरण संबंधित जनपदों को नियमानुसार उनकी ओर से प्राप्त मांग के अनुरूप किया जाएगा। इसके लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। साथ ही धनराशि से किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा कर शासन को इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित और बेसहारा गोवंश की समस्या के समाधान के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानीय निकायों में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना और संचालन की नीति लागू की गई है।

जानकीपुरम में नाबालिग से आपत्तिजनक कृत्य के आरोप में 63 वर्षीय दादा गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। जानकीपुरम थाना क्षेत्र में करीब साढ़े चार वर्षीय बच्ची के साथ आपत्तिजनक कृत्य के आरोप में पुलिस ने उसके 63 वर्षीय दादा को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 30 जून 2026 को बच्ची की मां ने थाना जानकीपुरम में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी करीब साढ़े चार वर्ष की पुत्री के साथ उसके दादा राम रतन साहू द्वारा आपत्तिजनक कृत्य किया गया है। शिकायत मिलने के तत्काल बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा अपराध संख्या 117/2026, धारा 65(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 6 पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की विवेचना वरिष्ठ उपनिरीक्षक हरिदास चौरसिया को सौंपी गई।विवेचना के दौरान पुलिस ने वादिनी के बयान दर्ज किए और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही बच्ची से संबंधित चिकित्सकीय परीक्षण एवं उपलब्ध मेडिकल अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी राम रतन साहू के खिलाफ कार्रवाई की।पुलिस टीम ने 18 अगस्त 2026 को आरोपी राम रतन साहू को भवानी बाजार के पास से हिरासत में लिया। गिरफ्तार आरोपी की उम्र करीब 63 वर्ष बताई गई है। वह मूल रूप से ग्राम रनवोड़, पोस्ट घोघरा, थाना एवं तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ का निवासी है।

पारा में अवैध डेयरियों पर नगर निगम का कड़ा प्रहार, 197 पशु पकड़े गए

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। पारा क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर संचालित की जा रही अवैध दूध डेयरियों के खिलाफ नगर निगम ने मंगलवार को बड़ा अभियान चलाया। गत दिनों अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने गई नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम पर हुए हमले की घटना को गंभीरता से लेते हुए महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार स्वयं मौके पर पहुंचे और अभियान की निगरानी की। उनके निर्देश पर पुलिस बल, प्रवर्तन दल और कैटिल कैचिंग दस्ते की संयुक्त टीम ने बुद्धेश्वर से शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय रोड तक सघन कार्रवाई करते हुए कुल 197 पशुओं को पकड़कर अलग-अलग कांजी हाउस और गौशाला में निरुद्ध कराया।महापौर सुषमा खर्कवाल ने मौके पर अधिकारियों से कार्रवाई की जानकारी लेते हुए स्पष्ट किया कि शहर में नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से डेयरी संचालित करने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को अभियान को लगातार प्रभावी ढंग से चलाने और अवैध गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि शहर में कानून और निर्धारित नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित कराया जाएगा तथा सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।नगर आयुक्त गौरव कुमार के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में नगर निगम के प्रवर्तन दल, कैटिल कैचिंग दस्ते और पुलिस बल ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। नगर आयुक्त ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से अभियान की प्रगति और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखते हुए अवैध डेयरियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए और पकड़े गए पशुओं को निर्धारित स्थानों पर सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाए।अभियान के दौरान नगर निगम की टीम ने कुल 197 पशुओं को पकड़कर निरुद्ध कराया। इनमें 46 भैंसों को राधा उपवन गौशाला, 40 भैंसों को ठाकुरगंज कांजी हाउस, 31 भैंसों को पीजीआई कांजी हाउस, 33 भैंसों को आलमबाग कांजी हाउस तथा 46 भैंस और एक बड़ी पड़िया को ऐशबाग कांजी हाउस भेजा गया। नगर निगम की टीम ने कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से संचालित डेयरियों को चिन्हित करने के साथ पशुओं को हटाने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की।नगर निगम का यह विशेष अभियान बुद्धेश्वर, पारा, गढ़ियाना, ज्ञानेन्द्र विहार और शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय रोड के आसपास चलाया गया।

लखनऊ में ट्रेनिंग पार्टनर्स की समस्याओं पर मंत्री कपिल देव ने दिया समाधान का भरोसा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मुख्यालय में मंगलवार को प्रशिक्षण प्रदाताओं (ट्रेनिंग पार्टनर्स) की समस्याओं को लेकर बैठक हुई। प्रदेशभर से पहुंचे ट्रेनिंग पार्टनर्स ने अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के सामने रखा। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर प्रशिक्षण प्रदाताओं ने नारेबाजी भी की।

ट्रेनिंग पार्टनर्स का आरोप है कि उनकी कई जायज मांगों पर अधिकारियों की ओर से लंबे समय से सुनवाई नहीं हो रही है। भुगतान में देरी, लक्ष्य निर्धारण में अनियमितता और प्रशिक्षित युवाओं की परीक्षाएं नहीं होने जैसी समस्याओं के कारण प्रशिक्षण प्रदाताओं को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि कई लोग कर्ज के बोझ में दब चुके हैं और बार-बार शिकायत के बावजूद समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।

ट्रेनिंग पार्टनर अभय सिंह ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग भुगतान से संबंधित गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करना है। उनका कहना है कि कई वर्षों से भुगतान लंबित है। इसके अलावा प्रशिक्षण पूरा कर चुके युवाओं की समय पर परीक्षा नहीं होने से उनका प्लेसमेंट भी प्रभावित हो रहा है। प्रशिक्षण प्रदाताओं ने मांग की कि लंबित भुगतानों को जल्द जारी किया जाए और परीक्षा एवं प्लेसमेंट की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी कराई जाए। बैठक में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रशिक्षण प्रदाताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि उचित मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कौशल विकास सरकार की प्राथमिकता वाला विभाग है और कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

इस दौरान प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम और निदेशक पुलकित खरे ने भी ट्रेनिंग पार्टनर्स से वार्ता की। ट्रेनिंग पार्टनर्स एसोसिएशन की ओर से अभय सिंह, अमित, मोनिश, कार्तिकेय, त्रिगंत, रेहान, कमल रामलानी, कौशिक सक्सेना, विक्रम भट्ट, लवलेश श्रीवास्तव, विकास माहेश्वरी, राजेश कुमार तिवारी, वरुणेश द्विवेदी, प्रियांक गुप्ता, अरुण एरी, शनी राय और विवेक समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

ट्रेनिंग पार्टनर्स की प्रमुख मांगें

लक्ष्यपूर्ति की तरह भुगतान की भी हर महीने समीक्षा की जाए।

अनुबंध और निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार समय पर भुगतान किया जाए।

सभी भुगतान किस्तों को एक-दूसरे से स्वतंत्र किया जाए, ताकि पात्र प्रशिक्षण प्रदाता सभी किस्तों के बिल एक साथ पोर्टल पर भेज सकें।

जिन किस्तों के भुगतान के लिए प्रशिक्षण प्रदाता पात्र हैं, उनका भुगतान एक साथ किया जाए।

पिछले तीन वर्षों से लंबित चौथी भुगतान किस्त का प्रारूप UPSDM पोर्टल पर तत्काल तैयार किया जाए।

यूनिफॉर्म वितरण से संबंधित भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाए।

सीडीओ अनुमोदन की प्रक्रिया अधिकतम सात दिनों में पूरी की जाए।

प्रशिक्षण पूरा होने के सात दिन के भीतर मूल्यांकन कराने की जिम्मेदारी मिशन की हो।

टीपी द्वारा अपलोड किए गए प्लेसमेंट डेटा का सत्यापन 30 दिनों के भीतर किया जाए।

सिम स्वैप, सीडीआर और आईपीडीआर के विश्लेषण पर 143 पुलिसकर्मियों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौती के बीच पुलिस की तकनीकी दक्षता और विवेचना क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से कमिश्नरेट लखनऊ की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग शाखा की ओर से मंगलवार को 'सिम स्वैप तथा सीडीआर एवं आईपीडीआर का विश्लेषण' विषय पर विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में आयोजित यह कार्यशाला उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ में संपन्न हुई। प्रशिक्षण में कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों की साइबर हेल्प डेस्क, साइबर सेल, जोन स्तर की साइबर सेल तथा साइबर थाने में तैनात 143 अधिकारी और कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया।पुलिस आयुक्त तरुण गाबा के निर्देशन में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय अपर्णा कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार तथा पुलिस उपायुक्त मुख्यालय अमित कुमावत के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध शाहिदा नसरीन के निर्देशन में किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को आधुनिक तकनीकी संसाधनों के उपयोग के माध्यम से साइबर अपराधों की रोकथाम, विवेचना और डिजिटल साक्ष्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए और अधिक सक्षम बनाना रहा।प्रशिक्षण कार्यक्रम में साइबर विशेषज्ञ अनुज अग्रवाल ने प्रतिभागियों को सिम स्वैप, सीडीआर और आईपीडीआर से जुड़े महत्वपूर्ण तकनीकी, विधिक और प्रक्रियात्मक पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने साइबर अपराधों की जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों को सुरक्षित करने, उनका विश्लेषण करने तथा विभिन्न डिजिटल कड़ियों को जोड़कर संदिग्ध व्यक्तियों तक पहुंचने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया।कार्यशाला में सिम स्वैपिंग से जुड़े साइबर अपराधों की कार्यप्रणाली पर विशेष रूप से चर्चा की गई। प्रशिक्षक ने बताया कि सिम स्वैप के जरिए अपराधी किस प्रकार मोबाइल नंबर पर नियंत्रण हासिल कर साइबर अपराध को अंजाम दे सकते हैं। पुलिसकर्मियों को ऐसे मामलों में अपराध की प्रकृति समझने, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाने के महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी गई।प्रशिक्षण के दौरान सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) और आईपीडीआर (इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड) के वैज्ञानिक विश्लेषण पर भी विस्तार से जानकारी दी गई।

भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई सूची ने जो सियासी संकेत दिया है वह सबके समझ में आने वाली बात नहीं है

नितिन नबीन की बहुप्रतीक्षित टीम का आज आखिरकार ऐलान हो ही गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने संगठन में लंबे समय से चल रही कवायद को अंजाम देते हुए अपनी नई राष्ट्रीय टीम सामने रख दी है। इस टीम में अनुभव, क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक समीकरण और चुनावी जरूरतों का ऐसा मिश्रण तैयार किया गया है, जिसमें पार्टी के पुराने दिग्गजों से लेकर नए चेहरों तक को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इस पूरी कवायद में दो फैसले राजनीतिक चर्चा के केंद्र में हैं। एक तो अमित मालवीय को आईटी सेल प्रमुख की जिम्मेदारी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर भाजपा के शीर्ष संगठन में वापसी हुई है।

हम आपको बता दें कि आईटी और सोशल मीडिया सेल की कमान अब छत्तीसगढ़ के दीपक म्हास्के को दी गई है। वहीं अनिल बलूनी मीडिया प्रभारी की अपनी जिम्मेदारी पर कायम हैं। यानी भाजपा ने डिजिटल मोर्चे पर चेहरे में बदलाव किया है, लेकिन मीडिया प्रबंधन के मौजूदा ढांचे में निरंतरता बनाए रखी है। इस बदलाव को केवल संगठनात्मक फेरबदल मानना मुश्किल है। यह संकेत है कि नितिन नबीन डिजिटल और राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई में नई रणनीति और नए चेहरों के साथ उतरना चाहते हैं। साथ ही चूंकि नितिन नबीन छत्तीसगढ़ में पार्टी के प्रभारी रह चुके हैं ऐसे में वह जानते हैं कि उस राज्य के किस नेता की कार्यक्षमता का उपयोग कहां पर करना पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

इसके अलावा, स्मृति ईरानी की वापसी इस टीम का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश है। उन्हें उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। आक्रामक राजनीतिक शैली, संसदीय अनुभव और विपक्ष के खिलाफ मुखर राजनीतिक लड़ाई के लिए पहचाने जाने वाली स्मृति ईरानी को संगठन के शीर्ष स्तर पर लाना बताता है कि भाजपा उत्तर प्रदेश जैसे निर्णायक राज्य में राजनीतिक सक्रियता को और धार देना चाहती है।

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत पांडा, डी. पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, डॉ. भारती प्रवीण पवार, मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, एम. नागराजा, प्रो. तारिक मंसूर और डॉ. मधुचंद्र कर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। छह महिला उपाध्यक्षों की मौजूदगी से महिला प्रतिनिधित्व का संदेश भी स्पष्ट है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय महासचिवों की टीम में विनोद तावड़े, सुनील बंसल, बिप्लब कुमार देब, स्मृति ईरानी, डॉ. सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया शामिल हैं। संगठन के स्तर पर बीएल संतोष राष्ट्रीय महासचिव संगठन बने हुए हैं, जबकि शिवप्रकाश और सौदान सिंह को राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठन की जिम्मेदारी मिली है। इसका अर्थ है कि नबीन ने संगठन की अनुभवी मशीनरी को बनाए रखते हुए राजनीतिक मोर्चे पर अपनी टीम को विस्तार दिया है।

साथ ही 16 राष्ट्रीय सचिवों की सूची में भी व्यापक क्षेत्रीय संतुलन दिखाई देता है। कविता पाटीदार, के. सुरेंद्रन, डॉ. भोला सिंह, डॉ. प्रदीप वर्मा, जगदीश ईश्वरभाई पटेल, आम आदमी पार्टी से भाजपा में आये डॉ. संदीप पाठक और फांगनॉन कोन्याक, संगीता यादव, अनिल एंटनी, डॉ. एम. वेंकटेशन, मनोज तिग्गा, सिद्धार्थ शंभू, डॉ. स्वदेश सिंह, मृगांका देब बर्मन, रोहन गुप्ता और जय प्रकाश को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। इनमें दक्षिण, पूर्वोत्तर, पूर्वी भारत, हिंदी पट्टी और शहरी राजनीतिक पृष्ठभूमि, सभी को जगह मिली है।

नई टीम के अन्य हिस्से भी राजनीतिक संकेत दे रहे हैं। केंद्रीय कार्यालय प्रभारी तरुण चुग और केंद्रीय कार्यालय सचिव महेंद्र पांडे बनाए गए हैं। नॉर्थ-ईस्ट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी डॉ. संबित पात्रा और संयुक्त कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी राजीव बब्बर को दी गई है। सभी सेल्स के समन्वय की कमान विष्णु दत्त शर्मा को मिली है, जबकि ऋतुराज सिन्हा और विष्णु वर्धन रेड्डी संयुक्त समन्वयक होंगे।

मोर्चों की कमान भी सामाजिक और चुनावी विस्तार को ध्यान में रखकर तय की गई है। युवा मोर्चा के अध्यक्ष डॉ. हेमंग जोशी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष अमरपाल मौर्य, किसान मोर्चा के अध्यक्ष बंसीलाल गुर्जर, एससी मोर्चा के अध्यक्ष शिवेश कुमार राम, एसटी मोर्चा के अध्यक्ष डॉ. मन्नालाल रावत और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बसीत अली बनाए गए हैं। इससे भाजपा ने समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच संगठनात्मक पहुंच को मजबूत करने की कोशिश की है।

विजन 2047 की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़: उद्योगों से आत्मनिर्भर और समृद्ध भविष्य की नई पहल

इस यूनिट से 4650 लोगों को रोजगार मिलेगा। टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को देश-विदेश में नई पहचान दिलाने यह अहम कदम है।

छगन लाल लोन्हारे

छत्तीसगढ़ आज औद्योगिक विकास के ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां विकास का उद्देश्य केवल नए उद्योग स्थापित करना नहीं, बल्कि रोजगार, निवेश, आधुनिक तकनीक और क्षेत्रीय संतुलन के माध्यम से प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए पारदर्शी, निवेश-अनुकूल और रोजगारोन्मुख वातावरण तैयार किया है। वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन के मार्गदर्शन में नई औद्योगिक नीतियों ने निवेशकों का विश्वास मजबूत किया है और छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों की कतार में खड़ा करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं।

25 जून 2026 में टेक्सटाइल पार्क की पहली यूनिट का किया भूमिपूजन

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने 25 जून 2026 में टेक्सटाइल पार्क की पहली यूनिट का भूमिपूजन किया। तमिलनाडु की स्विफ्ट टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड 235 करोड़ रुपए के निवेश से यहां गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है। इस यूनिट से 4650 लोगों को रोजगार मिलेगा। टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को देश-विदेश में नई पहचान दिलाने यह अहम कदम है।

प्रदेश में 3,009 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुईं, जिनसे 50,807 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार

बीते ढाई वर्षों में राज्य को 264 औद्योगिक परियोजनाओं से लगभग 8.22 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे 1.72 लाख से अधिक रोजगार सृजन की संभावना है। इनमें से 154 परियोजनाएं निर्माण, भूमि आवंटन अथवा उत्पादन के चरण तक पहुंच चुकी हैं, जबकि कई इकाइयां पहले ही उत्पादन प्रारंभ कर चुकी हैं। इसी अवधि में प्रदेश में 3,009 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुईं, जिनसे 50,807 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला। यह दर्शाता है कि सरकार की औद्योगिक नीतियां केवल कागज़ों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि धरातल पर परिणाम दे रही हैं।

विनिर्माण इकाइयों को 100 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र को 150 प्रतिशत तक वित्तीय प्रोत्साहन

राज्य सरकार द्वारा लागू औद्योगिक विकास नीति 2024-30 ने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। विनिर्माण इकाइयों को 100 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र को 150 प्रतिशत तक वित्तीय प्रोत्साहन, एमएसएमई और सेवा उद्योगों को पहली बार विशेष लाभ, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फार्मा जैसे भविष्य के क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज तथा स्थानीय युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने वाले प्रावधान इस नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं। यही कारण है कि नवा रायपुर में देश का पहला एआई डेटा सेंटर एसईजेड और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश जैसी बड़ी पहलें आकार ले रही हैं।

ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। 150 से अधिक सेवाओं वाला नया सिंगल विंडो सिस्टम, निवेशकों के लिए एआई आधारित वाणी प्रणाली, 500 से अधिक प्रशासनिक सुधार तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण निवेशकों के लिए बेहतर माहौल तैयार कर रहा है। औद्योगिक विकास का लाभ प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचे, इसके लिए राज्य में 23 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए तथा 15 जिलों में 26 नए औद्योगिक कार्य स्वीकृत किए गए हैं। सरोरा में प्लास्टिक पार्क और नवा रायपुर में टेक्सटाइल, फार्मा एवं रेडीमेड गारमेंट पार्क जैसे प्रयास औद्योगिक आधार को और मजबूत बना रहे हैं।

सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक रोजगार सृजित करना और निवेश को तेजी से धरातल पर उतारना

हाल ही में विजन 2047 औद्योगिक विकास की संभावनाएं विषयक चर्चा में उद्योगमंत्री लखन लाल देवांगन ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक रोजगार सृजित करना और निवेश को तेजी से धरातल पर उतारना है, ताकि स्थानीय युवाओं को अधिकतम अवसर मिल सकें। आने वाले वर्षों के लिए सरकार निर्यात नीति, स्टार्टअप एवं नवाचार नीति, कौशल विकास, इंटर्नशिप, एमएसएमई सशक्तिकरण और बस्तर-सरगुजा जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, प्रदेश के युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना है।

छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम और बिज़नेस-फ्रेंडली माहौल में निवेशकों के बढ़ते भरोसे

राज्य में नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद पिछले 18 महीनों में 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का वादा मिला है, जिससे अलग-अलग सेक्टर में 1.6 लाख से ज़्यादा रोज़गार के अवसर पैदा होने की संभावना है। टेक्सटाइल और कपड़ों के अलावा, राज्य ने डेटा सेंटर, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी बड़े निवेश आकर्षित किए हैं। यह छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम और बिज़नेस-फ्रेंडली माहौल में निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दिखाता है।

नवा रायपुर में आधुनिक टेक्सटाइल पार्क की स्थापना

राज्य में वस्त्र एवं परिधान उद्योग को प्रोत्साहित करने नवा रायपुर में आधुनिक टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है। इसके 81 एकड़ क्षेत्र में 2758 वर्गमीटर से लेकर 38 हजार 180 वर्गमीटर आकार के भूखंड उपलब्ध हैं। टेक्सटाइल, गारमेंट एवं परिधान उद्योग, तकनीकी वस्त्र (ज्मबीदपबंस ज्मगजपसमे) तथा इनके सहायक एवं पूरक उद्योगों की स्थापना के लिए निवेशकों को यहां सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

प्रदेश आज उद्योगों की नई उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार

विजन 2047 की दिशा में छत्तीसगढ़ का यह औद्योगिक अभियान केवल आर्थिक विकास की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे भविष्य का निर्माण है जहां निवेश, नवाचार, रोजगार और समावेशी विकास मिलकर आत्मनिर्भर, विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव रख रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन के प्रयासों से प्रदेश आज उद्योगों की नई उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है।

लेखक संयुक्त संचालक, जनसंपर्क हैं

व्यंग्य

शान से विदाई

भारत के पदकों में सबसे ज्यादा योगदान एथलेटिक्स एवं पैरा-एथलेटिक्स का रहा, जिसमें 16 मेडल हासिल हुए। मगर, भारत की शान बढ़ाने का सबसे ज्यादा श्रेय बॉक्सरों को है, जिन्होंने सात स्वर्ण सहित 10 पदक जीते।

कॉमनवेल्थ गेम्स से भारतीय दल ने शान से विदाई ली है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 11 दिन के इस आयोजन के आरंभिक दिनों में पदक तालिका में पिछड़े रहने के कारण भारत में मायूसी छायी रही, लेकिन अंतिम दो दिनों में भारतीय खिलाड़ियों ने कहानी पलट दी। आखिरकार 13 स्वर्ण, 17 रजत, और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 मेडल्स के साथ भारत चौथे नंबर आ पहुंचा। अधिक खुशी की बात यह है कि भारत के पदकों में सबसे ज्यादा योगदान एथलेटिक्स एवं पैरा-एथलेटिक्स का रहा, जिसमें तीन स्वर्ण सहित 16 मेडल हासिल हुए। मगर, भारत की शान बढ़ाने का सबसे ज्यादा श्रेय बॉक्सरों को है, जिन्होंने सात स्वर्ण सहित 10 पदक जीते।

इस सिलसिले में इस उल्लेख से नहीं बचा जा सकता कि सात स्वर्ण पदक विजेता बॉक्सरों में से पांच सिर्फ एक शहर यानी हरियाणा के भिवानी से आते हैं। उनमें भी चार महिला बॉक्सर हैं। इस सफलता को बेशक वहां बने खेल ढांचे और भिवाणी बॉक्सिंग क्लब के प्रमुख जगदीश सिंह की मेहनत का परिणाम माना जाएगा। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में निशानेबाजी, कुश्ती, टेबल टेनिस और बैडमिंटन जैसे कई ऐसे खेल शामिल नहीं हुए, जिनमें भारत की मजबूत उपस्थिति रहती है। दरअसल, यह आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में होना था, जिसने ऐन वक्त पर कदम वापस खींच लिए। तब ग्लासगो में एक तरह से इसके आयोजन की रस्म-अदायगी की गई। इसलिए इस बार के गेम्स को ज्यादा वजन भी नहीं दिया गया है।

वैसे भी कॉमनवेल्थ गेम्स ओलिंपिक्स कैलेंडर का हिस्सा नहीं हैं, जिससे उन्हें ओलिंपिक्स या एशियाड जैसा महत्त्व नहीं दिया जाता। ब्रिटेन का रुतबा घटने के साथ-साथ कॉमनवेल्थ भी हाशिये पर पहुंच गया है। ऐसे में देश और खिलाड़ी इन खेलों को एक तरह से बड़े परिदृश्य के पूर्वाभ्यास के रूप में लेते हैं। इसे ध्यान में रखें, तो अगले 19 सितंबर से जापान के नागोया में होने जा रहे एशियन गेम्स के मद्देनजर ग्लासगो में भारतीय दल के प्रदर्शन को आशाजनक माना जाएगा। एशियाड में अधिक कड़ी प्रतिस्पर्धा में भी क्या देश की आशाओं पर भारतीय खिलाड़ी खरे उतरेंगे, इसे देखने पर सबकी नजरें रहेंगी।

ब्लॉग

पाठकों में फिर से रूचि जगाना: किताबों को फिर से बैठक कक्ष में जगह देना

सुअर्चना शर्मा अवस्थी और युवराज मलिक

भारत में शिक्षा पर चर्चा लंबे समय से पहुँच पर केंद्रित रही है - यानि स्कूलों तक, किताबों तक, डिजिटल संसाधनों तक पहुँच। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन जब हम भारतीय शिक्षा के एक नए चरण की दहलीज पर खड़े हैं, तो हमारे सामने एक और इतना ही जरूरी सवाल है:

क्या हम ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, जो पढ़ती है?

यह ऐसा सवाल है - जो सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इसके निहितार्थ गहरे हैं - जिसने राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय (आरईपी) या राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की। इस प्लेटफ़ॉर्म की परिकल्पना केवल एक डिजिटल संग्रहालय के रूप में नहीं, बल्कि घर, स्कूल और समुदाय के स्तर पर भारत की पढ़ने की संस्कृति को समृद्ध करने के जीवंत प्रयास के रूप में की गयी थी।

आज, आरईपी में 23 भाषाओं में 7,000 से ज्यादा चयनित किताबें मौजूद हैं, जो सैकड़ों प्रकाशकों के साथ साझेदारी में विकसित की गई हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विज़न के अनुरूप हैं। लेकिन इसका उद्देश्य कभी भी एक ऐसा संग्रह बनाना नहीं था, जो लगातार बढ़ता ही जाए। इसके पीछे एक सोच-समझकर अपनाया गया तरीका है: एक ऐसा संग्रह बनाए रखना, जो चयनित, प्रासंगिक और जीवंत हो - जिसे लगातार अद्यतन किया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण किताबें जोड़ी जाती हैं और अप्रासंगिक किताबों को हटाया जाता है। पैमाना मायने रखता है, लेकिन प्रासंगिकता, गुणवत्ता और लगातार जुड़ाव अधिक महत्वपूर्ण हैं।

भारत के कई बच्चों के लिए - खासकर ग्रामीण, अर्ध-शहरी और पिछड़े क्षेत्रों में - पाठ्यपुस्तकों के अलावा अन्य किताबों तक पहुंच एक बड़ी चुनौती है। सबसे नज़दीकी किताब की दुकान कई किलोमीटर दूर हो सकती है। स्कूल के पुस्तकालय में या तो किताबें पुरानी होती हैं या स्कूल अवधि के बाद उपलब्ध नहीं होती हैं। इन बच्चों के पास कल्पना तो है, लेकिन पठन-सामग्री मौजूद नहीं है।

राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय इस कमी को पूरा करता है: एक बच्चा, चाहे वह कहीं भी रहता हो या उसके परिवार का आय स्तर कुछ भी हो, अब अपने घर में पहले से मौजूद उपकरण के जरिए हजारों किताबों के पुस्तकालय तक पहुँच सकता है। बच्चे कभी भी और कहीं भी इन किताबों को पढ़ सकते हैं। यह हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषाओं में किताबों पढ़ने का भी अवसर देता है।

लेकिन यह समझना भी उतना ही ज़रूरी है कि यह पहल असल में क्या नहीं है।

यह छोटे बच्चों को ज्यादा समय तक स्क्रीन के सामने बिठाने का प्रयास नहीं है। यह परिवारों के लिए एक आमंत्रण है कि वे अपने पास मौजूद उपकरणों का अधिक सार्थक उपयोग करें - उस समय को साझा और समृद्ध अनुभव में बदलें, जो अन्यथा निष्क्रिय होकर, अकेले बैठकर या हानिकारक स्क्रॉलिंग या चीजें देखने में बीत जाता है।

माता-पिता का छोटे बच्चे को ज़ोर से पढ़कर सुनाना।

बड़े भाई/बहन का कहानी सुनाना।

परिवार का साथ बैठकर पढ़ने के लिए समय निकालना।

ऐसे समय में जब स्क्रीन अक्सर लोगों को एक-दूसरे से दूर करके अपने में ही उलझाए रखती है, किताबें - जिन्हें इन्हीं उपकरणों के ज़रिए पढ़ा जा सकता है - लोगों को फिर से एक साथ लाने की ताकत रखती हैं।

पढ़ने को स्क्रीन टाइम नहीं, बल्कि पारिवारिक समय बनाना।

राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय का उद्देश्य प्लेटफॉर्म के आयामों से कहीं अधिक गहरा है: इसका मकसद पढ़ने की आदत को फिर से घर के बैठक कक्ष में लाना है।

पढ़ना सिर्फ एक शैक्षणिक गतिविधि नहीं है। यह एक सामाजिक और भावनात्मक गतिविधि भी है। जब परिवार के सदस्य या दोस्त साथ में पढ़ते हैं, तो वे बातचीत, सहानुभूति और सोचने-समझने के लिए जगह बनाते हैं - यह साथ मिलकर ध्यान देने का एक ऐसा गुण है, जो ऐप-सूचना और रोज़मर्रा की ज़रूरतों में बंटी ज़िंदगी में अब कम ही देखने को मिलता है। इस बारे में हुए अध्ययन लगातार बताते हैं कि जिन बच्चों को पढ़कर सुनाया जाता है और जो अपने आस-पास बड़ों को पढ़ते हुए देखते हैं, उनमें न सिर्फ़ पढ़ने-लिखने की बेहतर समझ विकसित होती है, बल्कि उनकी अंदरूनी दुनिया भी ज़्यादा समृद्ध होती है।

आरईपी अंतरपीढ़ी सहयोग की संभावनाएं भी खोलता है। युवा पाठक अपने दादा-दादी या नाना-नानी को पढ़कर सुना सकते हैं। किशोर अपने बड़ों की पसंदीदा कहानियों को पढ़ सकते हैं। ऐसा करने पर, पढ़ना सिर्फ़ अकेले में किया जाने वाला या मजबूरी का काम नहीं रह जाता, बल्कि कुछ और ही बन जाता है - इसे मेरा समय के साथ-साथ हमारा समय भी कहा जा सकता है।

ऐसा करने पर, पढ़ना सिर्फ़ अकेले में किया जाने वाला या मजबूरी का काम नहीं रह जाता, बल्कि कुछ और ही बन जाता है - इसे मेरा समय के साथ-साथ हमारा समय भी कहा जा सकता है।

एक समाज के रूप में, हमें अपने आप से एक आसान, लेकिन गहन सवाल पूछना चाहिए: क्या हम स्क्रीन के निष्क्रिय उपयोग का एक हिस्सा वापस ले सकते हैं और उसे उपयोगी पढ़ाई में बदल सकते हैं? हमारा मानना है कि जवाब हाँ है - यदि हम किताबें उपलब्ध कराएं, उन्हें आकर्षक बनाएं और पढ़ाई को बोझ नहीं, बल्कि अपनी पसंद का काम बनाएं।

शिक्षकों के साथ काम करना: अगला चरण

राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय अपने अगले चरण में प्रवेश कर रहा है, लेकिन शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष और स्कूल के अग्रणी सिर्फ़ सीखने-सिखाने में मदद करने वाले नहीं होते, बल्कि वे संस्कृति को आकार देने वाले भी होते हैं। पढ़ने की जो आदतें बच्चे स्कूल में विकसित करते हैं, वे अक्सर जीवन भर उनके साथ रहती हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा सुझाई गई किताबें एक युवा व्यक्ति की सोच का दिशा बदल सकती हैं।

स्कूल जीवन में आरईपी के अर्थपूर्ण समावेश के लिए कई स्तरों पर सोच-समझकर कोशिशें करनी होंगी:

पुस्तकालय-कक्षाओं को केवल निगरानी वाले अध्ययन कक्ष के बजाय, सक्रिय ज्ञान-प्राप्ति स्थान के रूप में पुनर्जीवित करना,

निर्देश के अनुसार पढ़ने और कहानी सुनाने वाले सत्रों को प्रोत्साहित करना, जहां शिक्षक अपनी पसंदीदा किताबें साझा करें

सहपाठियों के नेतृत्व में किताब पर चर्चा और पठन-समूह बनाना, जिससे पढ़ने की आदत पर छात्रों को अपना अधिकार महसूस हो

पढ़ाई को स्कूल जीवन की दैनिक दिनचर्या में शामिल करना, ताकि यह सुबह की सभा जितना ही स्वाभाविक लगे

विभिन्न लेखन विधियों को समझकर लेखन कौशल में सुधार करना।

एक जीवंत और विकसित होता पुस्तकालय

पारंपरिक पुस्तकालय अपने अलमारियों में स्थिर और भौतिक आयामों से बंधे होते हैं - इसके विपरीत राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय को गतिशील बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह आपके हाथ में किताबों का खजाना है। यह पाठकों को यह व्यक्त करने भी मौका देता है कि कौन सी अन्य किताबें जोड़ी जानी चाहिए। उपलब्ध किताबें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति के बारे में भी हैं, जिसे युवा पीढ़ी को जानना चाहिए।

इसका बहुभाषी आधार भी उतना ही अहम है। एक बच्चा उस भाषा में सबसे बेहतर और स्वाभाविक रूप से पढ़ता है, जिसमें वह सोचता है। 23 भाषाओं में किताबें पेश करके - आगे और विस्तार करने की महत्वाकांक्षा के साथ - आरईपी भारत की भाषाई विविधता का सम्मान करता है, इसे केवल एक प्रबंधनीय चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक रचनात्मक ताकत के रूप में देखता है, जिसका जश्न मनाया जाना चाहिए। इस प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूद हर भाषा एक दरवाज़े की तरह है, जिससे गुज़रकर बच्चा एक नई दुनिया में कदम रख सकता है। 8 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए, यह प्लेटफ़ॉर्म माता-पिता और शिक्षकों को कहानियाँ ज़ोर-ज़ोर से पढ़कर सुनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

अंततः, राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय की सफलता केवल डाउनलोड और पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या से तय नहीं होगी, भले ही ये संकेत महत्वपूर्ण हैं। इसकी सफलता इस बात से तय होगी कि क्या पढ़ना फिर से एक आदत बन जाता है - घरों में, स्कूलों में, भारत के विविध और अद्वितीय समुदायों के एकांत कोनों में। किसी दूर-दराज़ इलाके के बच्चे की आँखें तब चमक उठती हैं, जब वह ऐसी किताब पढ़ता है, जिसके बारे में उसने सिर्फ़ सुना होता है।

यह प्लेटफ़ॉर्म राष्ट्रीय काव्य उत्सव जैसी गतिविधियाँ भी आयोजित करता रहता है और नागरिकों से कहानी सुनाने में योगदान देने का आह्वान भी करता है। राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय में और भी कई मज़ेदार और दिलचस्प गतिविधियाँ लगातार शामिल होती रहेंगी।

भारत हमेशा से कहानियों की सभ्यता रहा है। लिखित रूप से पहले की मौखिक परंपराओं से लेकर हिंदी, संस्कृत, तमिल, बंगाली, मराठी और अन्य कई भाषाओं के महान साहित्य तक, इस देश में कहानियों की कभी कमी नहीं रही। आज संकट कहानियों पर नहीं, बल्कि उन्हें खोजने की आदत पर है - यानि शांति से बैठकर किसी वाक्य को समझने और किसी किताब को वह समय देने की इच्छाशक्ति, जिसकी वह मांग करती है।

जब नागरिक पढ़ते हैं, तो देश आगे बढ़ता है।

-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

(लेखक भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में अपर सचिव हैं। लेखक नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया के निदेशक हैं।)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीआरडी जवानों के लिए शुरू की कैशलेस चिकित्सा योजना, 600 रुपये होगा ड्यूटी भत्ता

आर्यावर्त संवाददाता

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) जवानों की बड़ी सौगात दी। इन जवानों को सपरिवार प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये मुफ्त इलाज से आच्छादित करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने उनके दैनिक ड्यूटी भत्ता में वृद्धि करने की घोषणा की। अपने कार्यकाल में इसके पूर्व तीन बार ड्यूटी भत्ता बढ़ा चुके मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में आयोजित पीआरडी जवानों के सम्मेलन में चौथी बार वृद्धि का ऐलान करते हुए कहा कि अब पीआरडी जवानों को 500 रुपये की जगह प्रतिदिन 600 रुपये ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। मंगलवार को योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित पीआरडी जवानों के सम्मेलन में

सीएम योगी ने पीआरडी स्वयंसेवकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा कार्ड का वितरण कर 'मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना' का शुभारंभ करने के साथ ही रिमोट का बटन दबाकर लखनऊ में करीब 23 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बहुमंजिला पीआरडी बैरक का शिलान्यास भी किया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने पीआरडी जवानों के लिए नई घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1948 में गठित पीआरडी के स्वयंसेवकों को 2019 तक 250 रुपये दैनिक ड्यूटी भत्ता मिलता था। 2019 में उन्होंने इसे बढ़ाकर 375 रुपये और 2022 में बढ़ाकर 395 रुपये किया था।

2025 में भत्ता वृद्धि फिर से की और बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, 'अब पीआरडी स्वयंसेवकों का भत्ता 500 से रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन करने जा रहे हैं।' उन्होंने कहा पीआरडी जवानों के लिए 75 वर्ष में भत्ता राशि 250 रुपये तक ही थी जबकि विगत 8 वर्ष में ही यह 250 से बढ़कर 600 रुपये होने जा रहा है। यह वृद्धि सौ प्रतिशत से भी अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित कराने के लिए पुलिस और प्रशासन के सहयोग में पीआरडी के स्वयंसेवक अपनी भूमिका समर्पण भाव से निभाते हैं। पर, इसके बावजूद 2017 के पहले तक उन्हें ड्यूटी नहीं मिलती थी। जबकि आज उनके महत्व को समझा गया तो ड्यूटी के लिए जवान कम पड़ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा हो, महाकुंभ, दीपोत्सव, रंगोत्सव, ट्रैफिक संचालन में सहयोग, चुनाव ड्यूटी हो या अन्य किसी भी कार्य में प्रशासन-पुलिस का सहयोग, पीआरडी जवानों ने अनुशासन, समर्पण और सेवाभाव से कार्य किया। सीएम योगी ने कहा कि पीआरडी स्वयंसेवकों के प्रदेश को प्रगति में योगदान, समर्पण और सेवाभाव को धन्यवाद देते हुए प्रदेश सरकार उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस इलाज की सुविधा दे रही है।

इसके अंतर्गत 31 हजार से अधिक पीआरडी स्वयंसेवकों को किसी भी सरकारी और सरकार से इम्पैनल्ड अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा प्रतिवर्ष मिलेगी। पीआरडी जवानों की संख्या को उनके परिवार के लिहाज से औसत रूप में देखें तो 1 लाख 55 हजार से अधिक सदस्य इससे लाभान्वित होंगे।

सीएम योगी के नेतृत्व में कई गुना बढ़ा पीआरडी का बजट : डॉ. तोमर

पीआरडी जवानों के सम्मेलन में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल, डॉ. सोमेंद्र तोमर ने कहा कि पीआरडी के जवान शांति, सुरक्षा और जनसेवा के मजबूत आधार हैं। महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद 2017 के पहले पीआरडी का बजट मात्र 23 करोड़ रुपये था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इसे कई गुना बढाया गया। आज पीआरडी का बजट 543 करोड़ रुपये हो चुका है।

इस अवसर पर जिला पंचायत की प्रशासक साधना सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, श्रीराम चौहान, विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, प्रदीप शुक्ल, सरवन निषाद, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, पीआरडी विभाग के सचिव सुहास एलवाई, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता, पूर्व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

दस स्वयंसवेकों को सीएम योगी के हाथों मिला कैशलेस चिकित्सा कार्ड

प्रांतीय रक्षक दल के सम्मेलन में दस स्वयंसेवकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों कैशलेस चिकित्सा कार्ड प्राप्त हुआ। इनमें गोरखपुर के अजय, भीमसेन, धीरेंद्र, उमेश कुमार, लखनऊ की स्नेहलता रावत, अनामिका वर्मा, कुशीनगर की चंदा भारती, मऊ के जय सिंह, चंदौली के मो. शाकिर और वाराणसी के किशन गुप्ता शामिल रहे।

मुजाहिद कैसे बनते हैं? मेरठ के इस मदरसे में आठ साल पढ़ने वाला जफर पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुपों से भी जुड़ा

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आया जैश-ए-मोहम्मद से प्रभावित बिहार के पूर्णिया निवासी मोहम्मद जफर आठ साल मेरठ में रहा था। उसने यहां कोतवाली क्षेत्र के एक मदरसे में रहकर पढ़ाई की थी। बीते 14 अगस्त को एटीएस ने हापुड़ के शेरपुर गांव स्थित मस्जिद के पास से दो संदिग्धों को हिरासत में लिया था। आशंका जताई जा रही है कि संदिग्ध मोहम्मद जफर के करीबी हो सकते हैं। मौके पर मिली बाइक सरधना निवासी कादर अब्दुल सत्तार की थी।

कोतवाली क्षेत्र के मदरसे में जफर वर्ष 2016 से 2023 तक पढ़ा था। उस दौरान वह मेरठ में ही रहता था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। शुरुआत में मस्जिद में मदरसा चलने की सूचना मिली थी। वहां जाकर पड़ताल की गई तो मस्जिद में एक मुअज्जिन मिले। उनका कहना था कि इमाम इस दौरान मस्जिद में नहीं हैं। वही इस संबंध में जानकारी दे पाएंगे। इमाम से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद जफर के बारे में मदरसे के शिक्षक जानकारी दे पाएंगे। यह भी पता चला कि मदरसा मस्जिद से कुछ दूर संचालित होता है।

मदरसे के शिक्षक से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वह 12 वर्ष से मदरसे में शिक्षक हैं। हालांकि उन्होंने जफर के संबंध में जानकारी से अनभिज्ञता जताई। उन्होंने कहा कि उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए रजिस्टर देखने होंगे। मंगलवार को इस संबंध में जानकारी दे पाएंगे। पुलिस भी इस मामले से अनभिज्ञता जताती रही।

आतंकी कनेक्शन और मेरठ का पुराना नाता

आतंकी कनेक्शन रखने वाले आरोपियों का वेस्ट यूपी और मेरठ से पुराना नाता है। इस साल भी कई मामले सामने आ चुके हैं। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और सरदार उर्फ सरफराज ने इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से स्लीपर सेल तैयार कर रहे हैं।

इस वर्ष 13 मार्च को अंबाला में मेरठ के लिसाड़ी गेट निवासी अनस समेत तीन युवकों की गिरफ्तारी हुई थी। अनस दो साल पहले चंडीगढ़ में पाकिस्तानी नेटवर्क के संपर्क में आया था। इसके बाद पुलिस और एटीएस अलग-अलग स्थानों से 25 से अधिक मेरठ से संबंध रखने वाले युवाओं की गिरफ्तारी कर चुकी है।

कर्नाटक, कानपुर के बाद हापुड़ पहुंची एटीएस

स्वतंत्रता दिवस से पूर्व 13 अगस्त को एटीएस ने कर्नाटक के कलबुर्गी स्थित एक मीट फैक्टरी में काम करने वाले तालुक के उपलम गांव के पास से उत्तर प्रदेश के सीतापुर निवासी मोहम्मद समीर और सलमान को गिरफ्तार किया था। एटीएस ने समीर के कमरे से कुछ नक्शे भी बरामद किए थे।

इसके बाद कानपुर देहात के अकबरपुर से संदिग्ध गतिविधियां मिलने पर कानपुर देहात के अकबरपुर क्षेत्र से भाई-बहन और हापुड़ के शेरपुर स्थित मस्जिद के पास से दो संदिग्धों को हिरासत में लेने का मामला सामने आया था। समीर और सलमान उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य लोगों से संपर्क में थे। आशंका है कि जफर का सुराग उनसे पूछताछ के बाद एटीएस को मिला है।

सरधना की बाइक कैसे पहुंची हापुड़... जवाब बाकी

14 अगस्त को हापुड़ के शेरपुर गांव से दो संदिग्धों को हिरासत में लेने के बाद मौके से बाइक बरामद की गई थी। पकड़े गए संदिग्ध इसी बाइक पर सवार थे। एटीएस के पीछा करने पर वह मस्जिद की ओर भागे थे, तभी दबोच लिया गया था। कुछ लोगों ने बताया था कि ये मस्जिद के लिए चंदा एकत्रित कर रहे थे।

हापुड़ से पकड़े संदिग्धों के तार जफर से जुड़े होने की आशंका है लेकिन मौके से मिली सरधना निवासी कादर अब्दुल सत्तार के नाम से रजिस्टर्ड बाइक के बारे में भी पुलिस ठोस जानकारी नहीं दे पाई है। यह बाइक वहां कैसे पहुंची। इसका जवाब मिलना भी बाकी है।

सीओ कोतवाली संग्राम सिंह का कहना है कि उन्हें आधिकारिक रूप से मामले की जानकारी नहीं मिली है। एटीएस ने भी उनसे संपर्क नहीं किया है। हालांकि कोतवाली पुलिस जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है।

सोशल मीडिया पर खंगालता था जेहादी सामग्री

मेरठ के मदरसे में पढ़ाई के दौरान ही मोहम्मद जफर के मन में जेहादी विचार पनप रहे थे। तभी वह आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और उसके प्रमुख मसूद अजहर के बारे में पढ़ने लगा था। इसके बाद वह जेहाद और मुजाहिदों की शहादत से जुड़ी सामग्री देखने-पढ़ने लगा। धीरे-धीरे वह खुद मुजाहिद बनने की सोचने लगा। उसका मकसद ही मुजाहिद बनना था। एटीएस की तफ्तीश में इसका खुलासा हुआ है।

एटीएस के मुताबिक जफर केवल जेहादी भाषण और सामग्री तक सीमित नहीं रहा। वह सोशल मीडिया पर यह भी देखता था कि मुजाहिद कैसे बना जाता है और इसके बाद क्या करना होता है। वह जेहादी विचारधारा से जुड़ी सामग्री लगातार तलाशता और देखता था। मसूद अजहर के भाषणों से प्रभावित होकर उसके मन में मुजाहिद बनने की इच्छा और मजबूत होती गई। मोबाइल में तमाम ऐसे भड़काऊ भाषणों के वीडियो मिले हैं।

पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुपों से भी जुड़ा था

पूछताछ में उसने खुद स्वीकारा कि वह मसूद अजहर से प्रभावित है। यहां तक कि उसका कहना था वह एक बार मसूद से मिलना भी चाहता था। उसके मोबाइल फोन की जांच में कई पाकिस्तानी जेहादी व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। इन ग्रुपों में जेहाद और चंदे से जुड़ी उसकी बातचीत भी मिली। वह सोशल मीडिया के जरिये जेहाद और खिलाफत से जुड़े बयान भी साझा करता था।

"डायरिया से डर नहीं" कार्यक्रम को मिला केमिस्ट एसोसिएशन का साथ

पीएसआई इंडिया और केनव्यू के सहयोग से चलाया जा रहा कार्यक्रम

कार्यशाला में डायरिया रोकथाम पर हुई विस्तार से चर्चा

आर्यावर्त संवाददाता

मुजफ्फरनगर। 'डायरिया से डर नहीं' कार्यक्रम के तहत मंगलवार को स्थानीय एक होटल में पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इण्डिया) व केनव्यू के सहयोग से दवा व्यापारियों (केमिस्ट एसोसिएशन) की अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गयी। कार्यशाला की अध्यक्षता मुजफ्फरनगर केमिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक योगेश मदन ने की। कार्यशाला में यह तय हुआ कि डायरिया से किसी भी बच्चे की मौत न होने पाए, इसके लिए मिलकर जागरूकता से लेकर अन्य स्तर पर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे।

कार्यशाला में पीएसआई इंडिया की प्रतिनिधि कोमल घई और भारती ने संस्था और डायरिया से डर नहीं कार्यक्रम के बारे में सभी को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के 13 और बिहार के तीन जनपदों में चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों की डायरिया के कारण होने वाली मृत्युदर को शून्य करना और दस्त प्रबंधन को बढ़ावा देना है। केमिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री अक्षय मित्तल ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। संरक्षक योगेश मदन ने डायरिया को रोकने के लिए आस-पास के वातावरण में स्वच्छता, सही तरीके से हाथ धोना, स्तनपान आदि के बारे में जानकारी दी। एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलजीत सिंह ने डायरिया के लिए जिंक और ओआरएस के महत्व के बारे में बताया।

कार्यक्रम में केमिस्ट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष राजेश जुनेजा, विजेंद्र शर्मा, आशीष अग्रवाल, वरुण चौधरी, हर्ष भाटिया, रवि कौशिक सहित केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों व पीएसआई इंडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

नशेड़ी को काटते ही सांप का हो गया ऐसा हाल, टपकता खून और लड़खड़ाता युवक

आर्यावर्त संवाददाता

एटा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नशेड़ी युवक के हाथ में सांप ने काट लिया। सांप के काटते ही युवक झट से खड़ा हो गया। सांप ने इतनी जोर से काटा, कि वो युवक के हाथ पर ही लटक गया। अब ये युवक सांप को हाथ में लटका कर सड़क पर आ गया। इस युवक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

शहर के मेहता पार्क का बताया जा रहा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें नशे में धुत युवक के हाथ से सांप लटका दिखाई दे रहा है। सांप के काटने के दौरान युवक के हाथ से खून निकलता भी दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद युवक ने सांप को हटाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि वो लड़खड़ाते हुए सामान्य तरीके से नजर आ रहा है।

युवक की इस हरकत को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी के अनुसार युवक नशे का आदी बताया जा रहा है। वायरल वीडियो कोतवाली नगर क्षेत्र के मेहता पार्क का बताया जा रहा है। हालांकि, वायरल वीडियो की सत्यता और युवक की पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

मिजिल्स–रूबेला टीकाकरण अभियान का शुभारंभ, 5 से 10 वर्ष तक के बच्चों को लगेगा टीका

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। जनपद में मिजिल्स-रूबेला (एमआर) टीकाकरण अभियान का मंगलवार को शुभारंभ किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नारायणपुर स्थित स्टेला मॉरिस कॉन्वेंट स्कूल में अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत जिले के सरकारी शिक्षण संस्थानों, निजी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और मदरसों में कक्षा एक से पांच तक अध्ययनरत बच्चों को एमआर वैक्सीन की डोज दी जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान 5 से 10 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण 18, 20, 21, 24, 25, 27 और 28 अगस्त 2026 को कराया जाएगा। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी स्कूल अथवा मदरसे में ले जाकर एमआर का टीका अवश्य लगवाएं। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी ने बताया कि

खसरा और रूबेला संक्रामक वायरल रोग हैं, जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने-छींकने और संपर्क में आने से फैल सकते हैं। खसरे में तेज बुखार और शरीर पर लाल चकत्ते पड़ना प्रमुख लक्षण हैं। वहीं रूबेला सामान्यतः हल्का संक्रमण होता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं में इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसकी शुरुआत बुखार, नाक बहने और खांसी जैसे लक्षणों से भी हो सकती है। अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस) तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ समन्वय स्थापित कर सभी स्कूलों और मदरसों में कक्षा एक से पांच तक के बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित कराने को कहा है। शुभारंभ कार्यक्रम में प्रधानाचार्य मंजला दीपा, डॉ. संजय गुप्ता, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, डीपीएम, डीसीपीएम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दूबेपुर के अधीक्षक, बीपीएम, बीसीपीएम, एसएमओ, डब्ल्यूएचओ, जेएसआई, पीसीआई के जिला प्रतिनिधि सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं विद्यालय के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

छटपटाया, नीचे गिरा और खामोशी की नींद सोया नितिन, रात में पेट दर्द और मौत पर साथी छात्रों ने बयां की कहानी

आर्यावर्त संवाददाता

बांदा। बांदा शहर के झील का पुरवा स्थित बीएल विद्या मंदिर निजी आवासीय विद्यालय में रविवार रात दो छात्रों की हालत बिगड़ गई। सोमवार सुबह उनकी संदिग्ध हालात में उनकी मौत हो गई। दोनों को स्कूल स्टाफ अलग-अलग समय पर लेकर जिला अस्पताल पहुंचा था। परिजन का आरोप है कि छात्रों की मौत के बाद उन्हें तबीयत खराब होने की सूचना दी गई। परिजन ने विद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा भी किया।

गिरवां थाना क्षेत्र के सरस्वाह गांव निवासी सुनील का बेटा नितिन (12) आवासीय विद्यालय में कक्षा छह का छात्र था। रविवार रात करीब एक बजे उसे उल्टी और पेटदर्द की शिकायत हुई। स्कूल स्टाफ उसे अस्पताल ले गया लेकिन कुछ देर बाद वापस विद्यालय ले आया। हालत

में सुधार न होने पर उसे सुबह करीब सात बजे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि जिला अस्पताल के रिकॉर्ड में उसे रात में भी लाए जाने की कोई जानकारी दर्ज नहीं है।

इसी तरह चिल्ला थाना क्षेत्र के महेंदु गांव निवासी पुष्कर उर्फ जयकिशोर का बेटा अरुण कुशवाहा (9) कक्षा दो में पढ़ता था। उसे सोमवार सुबह करीब चार बजे उल्टी और पेट दर्द हुआ। स्कूल स्टाफ सुबह करीब छह बजे उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। लेकिन उसने भी रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सूचना पर तहसीलदार और बीएसए अव्यक्तराम जिला अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। अधिकारियों ने विद्यालय पहुंचकर पूरे घटनाक्रम और व्यवस्था की जानकारी ली। वहीं विद्यालय प्रबंधक ओमप्रकाश का कहना था कि बच्चों के बीमार होने पर उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया था। विद्यालय प्रशासन ने पूरी कोशिश की लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। उधर, सोमवार दोपहर करीब दो बजे विद्यालय के कक्षा चार के छात्र चंद्रपाल सिंह निवासी गिरवां की भी हालत बिगड़ गई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसकी हालत में सुधार है।

विद्यालय में रविवार शाम मोमोज और फिंगर चिप्स मंगाए गए थे। बताया जा रहा है कि अधिकांश बच्चों ने इसे खाया था। इसके बाद छात्रों की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई है। विद्यालय का एक छात्र ही महाराणा प्रताप चौक से दोनों चीजें लेकर आया था। ऐसे में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। रात में घर सूचना देने को कहते रहे बच्चे, नहीं कराई बात नितिन के साथ उसका छोटा भाई हर्ष कक्षा एक में इसी विद्यालय का छात्र है। वहीं अरुण का बड़ा भाई उत्कर्ष कक्षा पांच में पढ़ता है। दोनों के भाइयों ने परिजन को बताया कि उन्होंने रात में ही घर पर उनकी तबीयत खराब होने की सूचना देने को कहा था लेकिन स्कूल के बड़े सर ने बात नहीं कराई। सोमवार सुबह जिला अस्पताल से परिजन को बच्चों के बीमार होने की सूचना दी गई। परिजन अस्पताल पहुंचे तो दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। परिजन ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

छटपटाया, नीचे गिरा और मौत की नींद सो गया नितिन

बांदा के बीएल विद्या मंदिर आवासीय विद्यालय में दो छात्रों की संदिग्ध हालात में मौत के बाद छात्रावास में रहने वाले अन्य बच्चे भी सहमे हुए हैं। नितिन की मौत के बाद उसके खाली पड़े बेड को देखकर साथी छात्रों के चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा। कक्षा छह का छात्र विपिन रात में नितिन की तबीयत बिगड़ने से लेकर उसकी मौत तक का घटनाक्रम बता रहा है। उसके अनुसार छटपटाते हुए नितिन तख्त से नीचे गिरा और हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया।

विपिन के मुताबिक रात में नितिन को उल्टी और पेट दर्द हुआ था। इसके बाद बड़े सर के साथ उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। कुछ देर बाद नितिन को वापस छात्रावास लाया गया। इस दौरान उसकी हालत ठीक नहीं थी। वह कभी ऐंठता तो कभी हाथ-पैर पटकता रहा। विपिन और उसके साथियों ने कई बार उससे पूछा लेकिन नितिन कुछ बोल नहीं पाया। उसने केवल पानी पिलाने का इशारा किया। यह भी बताया कि कुछ देर बाद नितिन अचानक छटपटाते हुए तख्त से नीचे गिर गया। साथी छात्रों ने उसे उठाकर दोबारा तख्त पर लिटाया। इसके बाद वह सो गया। बच्चों को तब यह अंदाजा नहीं था कि नितिन हमेशा के लिए सो गया है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान नितिन का छोटा भाई हर्ष भी वहीं मौजूद था। हर्ष कक्षा एक में पढ़ता है। दोनों भाई बीते वर्ष से विद्यालय में पढ़ रहे थे।

सोमवार को दिनभर जांच-पड़ताल के दौरान भी बच्चे डरे-सहमे नजर आए। वहीं बच्चों के इन बयानों के बाद विद्यालय में रात के समय बच्चों की निगरानी, उपचार और परिजनों को सूचना देने की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

अरुण का भाई बोला, बड़े सर ने नहीं करने दिया फोन

कक्षा दो के छात्र अरुण की मौत के बाद उसके परिजन विद्यालय पहुंचे। उनके साथ अरुण का भाई उत्कर्ष भी था, जो इसी विद्यालय में कक्षा पांच में पढ़ता है। उत्कर्ष ने बताया कि रात में अरुण की हालत बिगड़ने पर वह उसके साथ था। उसने वार्डन से घर पर बात कराने के लिए कहा था लेकिन आरोप है कि बड़े सर ने फोन कराने से मना कर दिया।

अरुण के परिजन ने किया हंगामा

रविवार को मेडिकल कॉलेज में अरुण का शव देखने के बाद परिजन का सब्र जवाब दे गया। इसके बाद वे सीधे विद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने हंगामा काटा। उनका आरोप था कि आखिर क्यों उन्हें सही समय पर सूचना नहीं दी गई। उनके परिवार के कई सदस्य बांदा में ही रहते हैं, अगर समय पर उपचार मिल जाता तो उनके बेटे की जान बच जाती। हालांकि यहां उनके सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं मिला। आवासीय विद्यालय में संदिग्ध हालात में दो बच्चों की मौत हुई है। दोनों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। -शिवराज, अपर पुलिस अधीक्षक

मौत के बाद शरीर में क्या होता है: कितनी देर जिंदा रहता है ब्रेन, लिवर, शरीर नीला क्यों पड़ता है

अगर हमने अपने ऑर्गन डोनेट किए हैं तो ये हमारी मृत्यु के बाद किसी को जीवन दे सकते हैं। हमारी आंखें नए शरीर में जाकर फिर से खूबसूरत संसार को देख सकती हैं। हमारा दिल किसी और के शरीर में फिर से धड़क सकता है। फेफड़े फिर से सांस ले सकते हैं और हमारी किडनी किसी और के ब्लड से टॉक्सिन्स छान सकती है।

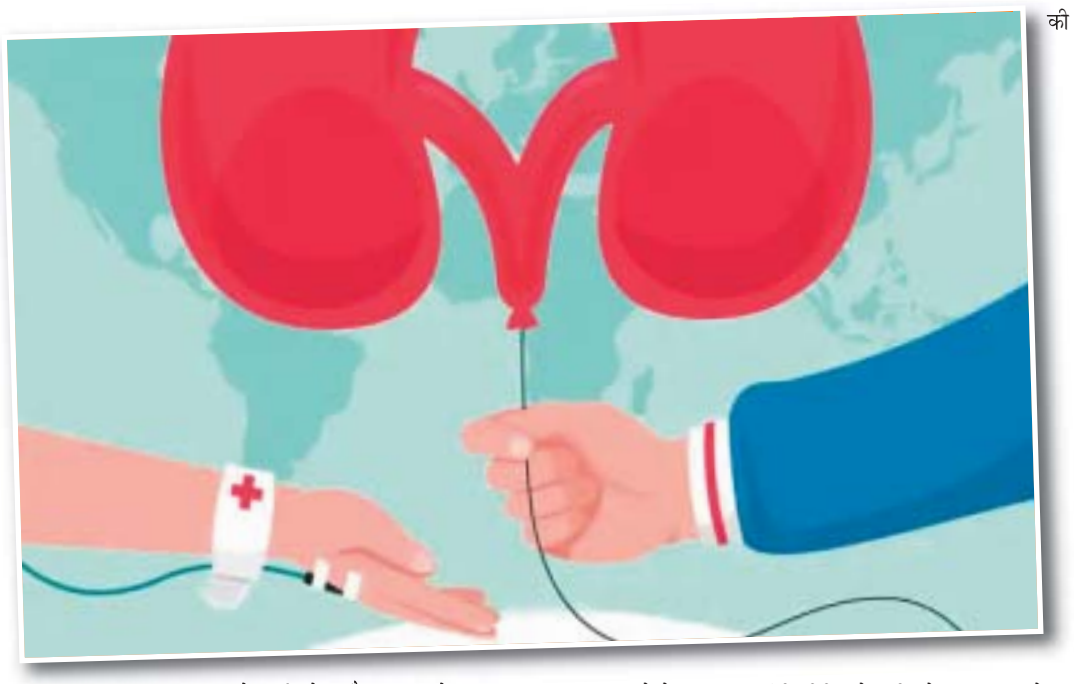

क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? पहली बार में यह आध्यात्मिक सवाल लग सकता है, जिसके बारे में गरुड़ पुराण से लेकर अलग-अलग दर्शन में अलग-अलग जवाब मिल जाएंगे। इनमें बताया जाता है मृत्यु के बाद हमारी आत्मा कैसे-कैसे और किस लोक में जाती है, वहां उसके साथ क्या होता है। लेकिन अगर इस विषय को वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो सवाल और उसके जवाब भी बिल्कुल बदल जाएंगे।

सवाल ये है कि मृत्यु के बाद शरीर का कौन सा अंग कितनी देर तक जीवित रहता है? इस क्षेत्र में हुई वैज्ञानिक रिसर्च से ही यह मुमकिन हुआ कि अब ऑर्गन डोनेशन के जरिए विज्ञान हर साल लाखों लोगों की जिंदगी बचा रहा है।

अगर हमने अपने ऑर्गन डोनेट किए हैं तो ये हमारी मृत्यु के बाद किसी को जीवन दे सकते हैं। हमारी आंखें नए शरीर में जाकर फिर से खूबसूरत संसार को देख सकती हैं। हमारा दिल किसी और के शरीर में फिर से धड़क सकता है। फेफड़े फिर से सांस ले सकते हैं और हमारी किडनी किसी और के ब्लड से टॉक्सिन्स छान सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 'मन की बात' के 99वें एपिसोड में अंगदान के महत्व पर बात की थी। इसके पहले हम भी ऑर्गन डोनेशन पर विस्तार से बात कर चुके हैं।

तो आज 'सेहतनामा' में हम बताएंगे कि मृत्यु के बाद हमारे शरीर में क्या होता है। साथ ही जानेंगे कि-

हर घंटा बीतने के साथ शरीर में क्या बदलता है?

शरीर के कौन से अंग कितने घंटे तक जीवित रहते हैं?

शरीर से बाहर निकलने पर कोई अंग कितनी देर तक जीवित रहता है?

मृत्यु के बाद शरीर में क्या होता है? आमतौर पर लोग मृत्यु का मतलब ये समझते हैं कि दिल ने धड़कना बंद कर दिया है। जबकि यह एक पूरी लंबी प्रक्रिया है। दिल की धड़कन थमने के बाद एक लंबी सीरीज में शरीर में बहुत कुछ हो रहा होता है। इस प्रोसेस को डीकंपोजिशन (क्षरण) कह सकते हैं।

मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद बीत रहे हर मिनट के साथ सभी अंगों में कुछ बदलाव हो रहे होते हैं। जैसे हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग ब्रेन जीवित रहने के लिए पूरी तरह ब्लड के जरिए मिल रही ऑक्सीजन पर ही निर्भर है। इसलिए दिल की धड़कन बंद होने के कुछ ही मिनटों बाद इसकी मौत हो जाती है। मृत्यु के तुरंत बाद शरीर में क्या बदलाव होते हैं, ग्राफिक में देखिए।

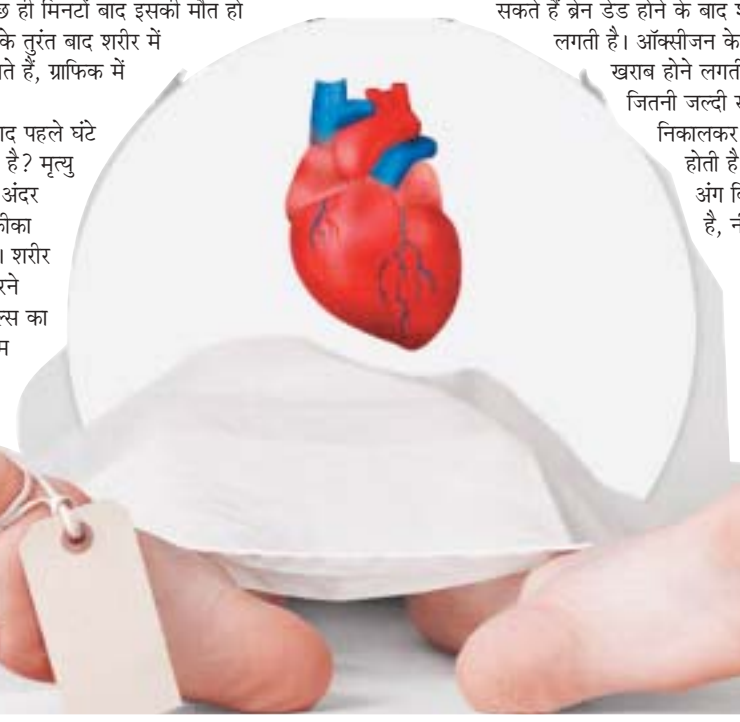

मृत्यु के बाद पहले घंटे में क्या बदलता है? मृत्यु के एक घंटे के अंदर त्वचा का रंग फीका पड़ने लगता है। शरीर का तापमान गिरने लगता है। मसल्स का लचीलापन खत्म होने लगता है। लिवर काम करना बंद कर देता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के बावजूद भी वह किसी तरह जीवित रहने की कोशिश कर रहा होता है। इसे ट्रांसप्लांट करने के लिए शरीर से तुरंत निकालना और प्रिजर्व करना जरूरी होता है।

मृत्यु के 2 से 6 घंटे के बीच क्या बदलता है? मृत्यु के बाद शुरुआती घंटे में लगभग हर जगह एक जैसी स्थिति होती है। उसके बाद की चीजें मौत के कारण, जलवायु, तापमान जैसे कई कारकों पर निर्भर करती हैं।

मृत्यु के 2 से 6 घंटे बाद शरीर में रासायनिक बदलाव होने लगते हैं, जिससे रिगर मॉर्टिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसमें शरीर की मसल्स अकड़ने लगती हैं। सबसे पहले शरीर की सबसे छोटी मसल्स प्रभावित होती हैं। इसका असर पलकों और जबड़े की मसल्स पर होता है।

मृत्यु के 6 से 12 घंटे बाद क्या होता है? मौत के बाद इतना समय बीतने पर पूरे शरीर की मसल्स अकड़कर कठोर हो जाती हैं। इस दौरान शरीर में ऑटोलिसिस नाम की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसमें हमारे शरीर की कोशिकाओं से एक खास एंजाइम निकलता है, जो टिशूज को ब्रेक करना और उसे खाना शुरू कर देता है। इसे ही डीकंपोजिशन कहते हैं। इसका मतलब है कि इस दुनिया में शरीर का मकसद पूरा हो गया है। अब अगर कोई इसकी अंतिम क्रिया नहीं भी करता है तो प्रकृति अपने तरीके से इसको धीरे-धीरे डीकंपोज करके खत्म कर देगी।

इस प्रोसेस के दौरान जब हमारे शरीर के सभी अंग एक-एक करके दम तोड़ रहे होते हैं, अगर इन्हें समय रहते शरीर से बाहर निकाल लिया जाए और प्रिजर्व कर लिया जाए तो ये किसी जरूरतमंद के शरीर में ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। इससे किसी शख्स को नया जीवन मिल सकता है।

मत्यु के कितनी देर बाद तक ट्रासप्लांट के लिए अंग निकाल सकते हैं ब्रेन डेड होने के बाद शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन के बिना सभी अंगों की फंक्शनिंग खराब होने लगती है। इसलिए इन्हें मत्यु के बाद जितनी जल्दी संभव हो सके, शरीर से बाहर निकालकर जरूरी ऑक्सीजन सप्लाई देनी होती है। शरीर में बने रहकर कौन सा अंग कितनी देर तक जीवित रह सकता है, नीचे दिए ग्राफिक में देखिए।

उपवास में खाएं ये ऑयल-फ्री हेल्दी स्नैक्स, बॉडी डिटॉक्स और एनर्जी बूस्ट होगी

शारदीय नवरात्रि में व्रत रखना न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह बॉडी डिटॉक्स का एक बेहतरीन तरीका भी है। न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल के अनुसार, व्रत के दौरान आप भुने मखाने, साबूदाना खिचड़ी, शकरकंद और फल-दही जैसे हेल्दी और ऑयल-फ्री स्नैक्स खा सकते हैं। ये स्नैक्स शरीर को एनर्जी देने के साथ-साथ इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं।

शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। इस त्योहार को 9 दिन कुछ लोग व्रत भी रखते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो नवरात्रि के दौरान उपवास रखना काफी फायदेमंद होता है। इससे शरीर के टॉक्सिंस आसानी से निकल जाते हैं। दरअसल, नवरात्रि के दौरान बॉडी डिटॉक्स करने का बेहतरीन समय होता है।

न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल कहती हैं कि व्रत के दौरान आप डाइट में हेल्दी स्नैक्स को शामिल कर सकते हैं। हेल्दी स्नैक्स खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है। इससे एनर्जी को बूस्ट करने में मदद मिलेगी। हालांकि, अगर आप उपवास रख रहे हैं तो स्नैक्स को लेकर सावधानी बरतने चाहिए। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि नवरात्रि में कौन से ऑयल फ्री स्नैक्स खाने चाहिए।

भुने मखाने

मखाने खाना हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है। उपवास रखा है तो आप इसे खा सकते हैं। आप इसे हल्का सा भूनकर खा सकते हैं।इसमें प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं, जो शरीर को सेहतमंद बनाए रखते हैं। भुने हुए मखानों को आप काली मिर्च और सेंधा नमक डालकर टेस्टी बना सकते हैं।

साबूदाना खिचड़ी

नवरात्रि में आप साबूदाना की खिचड़ी खा सकते हैं। इसे बनाना बेहद आसान होता है। इसे बनाना भी बेहद आसान होता है। साथ ही, आप इसमें मूंगफली, आलू और कुछ ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं। इस खिचड़ी को आप देसी घी से बना सकते हैं। इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी।

शकरकंद

शकरकंद में फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें नैचुरल शुगर पाई जाती हैं। इसे आप अच्छे से उबाल लें। इसके बाद सेंधा नमक और नींबू डालकर खा सकते हैं। यह ऑयल-फ्री स्नैक आपके उपवास को हेल्दी और ताजगी से भर देगा।

फल और दही

अगर आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो सेब, केला और अनार खा सकते हैं। आप इसे दूध और दही के साथ खा सकते हैं।इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और जीरा पाउडर डालें। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन को सही रखते हैं। फल शरीर को जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स प्रदान करते हैं।

ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए के लिए बेहतरीन हैं भारत की ये जगहें

घूमना तो बहुत लोगों को पसंद है लेकिन आजकल लोग ट्रैकिंग पर जाना पसंद करते हैं। इस दौरान उन्हें कुछ नया सीखने, एडवेंचर करने और प्रकृति में शांति से समय बिताने का मौका मिलता है। आज हम आपको उत्तराखंड में ट्रैकिंग की फेमस जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं।

ट्रैकिंग करना आजकल बहुत लोगों को पसंद है। ये प्रकृति के करीब जाने और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने का एक बेहतरीन तरीका है। ट्रैकिंग के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों, जंगलों, और प्राकृतिक सुंदरता में चलने का अवसर मिलता है। जहां हम ताजगी भरे वातावरण का आनंद ले सकते हैं। भागदौड़ और टेंशन के बीच कुछ समय के लिए घूमने या ट्रैकिंग पर जाना और वातावरण के बीच समय बिताना मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। जब हम प्रकृति के करीब होते हैं, तो हमें प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने का मौका मिलता है जो जिससे पॉजिटिविटी मिलती है।

लंबी ट्रैकिंग में कई दिनों तक चलना पड़ सकता है। उच्च ऊंचाई की ट्रैकिंग में पर्वतों की चढ़ाई शामिल होती है, जो व्यक्ति के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। जिसके लिए विशेष तैयारी की आवश्यकता जरूरी होती है।

खीरगंगा ट्रैक

धार्मिक स्थल खीरगंगा ट्रैकिंग के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। ये समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। खीरगंगा से होते हुए आप पिन पार्वती पास की चढ़ाई की जा सकती है। यहां बहुत से पर्यटक जाते हैं, जो स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का एक कारण बनते हैं। अक्टूबर का समय यहां जाने के लिए सही रहेगा। यहां ट्रैकिंग के लिए बहुत से रास्ते हैं। आप यहां पहुंचने के लिए स्थानीय गाइड ले सकते हैं।

डोडीताल ट्रैक

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित डोडीताल भी ट्रैकिंग के लिए बहुत लोकप्रिय है। संगम पट्टी गांव से से इसकी शुरुआत होती है। ट्रैकिंग के समय बर्फ से लदे हुए पेड़, गंगोत्री घाटी की चोटियां दिखाई देंगे। रास्ते में आने वाले कुछ गांव मेंरात बिता सकते हैं।

कुंजा खड़क ट्रैक

उत्तराखंड में कुंजा खड़क ट्रैक की शुरुआत पंगोट से होती है। देवदार के बड़े-बड़े पेड़ों के बीच जंगल से होकर ट्रैक पर जाने के सफर को आप इंजॉय कर सकते हैं। कुंज सड़क पर रापती नदी दिखेगी, जो नेपाल और भारत की सीमा को बांटता है। अक्टूबर इस जगह की ट्रैकिंग के लिए सबसे बेस्ट रहेगा।

सीताबनी ट्रैक

उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में सीताबनी मंदिर से इस ट्रैक की शुरुआत होती है और भोला मंदिर पर जाकर ये ट्रेक समाप्त होता है। ये घने जंगलों के बीच 8 से 10 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी होगी। रास्ते में घने पेड़ों के अलावा जंगली जानवर जैसे कि शेर, हाथी और भूल दिखाई दे सकते हैं। इसलिए यहां जाते समय कई सावधानी बरतनी चाहिए। आप लोकर गाइड को साथ में लेकर जरूर जाना चाहिए।

बिनसर जीरो पॉइंट

उत्तराखंड काबिनसरभी ट्रैकिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। यहां प्रकृति के सुंदर दृश्य के साथ ही आपको कई तरह के पक्षी देखने को मिलेंगे। ये ट्रैकबिनसरवन्यजीव अभयारण्य से होकर जाता है और ये काफी आसान ट्रैक है।

ट्रैकिंग से पहले बहुत सी तैयारी की जानी चाहिए सबसे पहले तो मेडिकल हेल्थ चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। इसके बाद सही कपड़ों का चयन, पर्याप्त मात्रा में पानी और खाना लेना और ट्रैकिंग के रास्ते के बारे में पूरी जानकारी लेना जरूरी है। आरामदायक जूते और मौसम के मुताबिक जगह प्लान करना जरूरी है। इसके अलावा, एक मेडिकल किट भी साथ ले जाना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी चोट लगने की संभावना रहती है।

रोजाना 100 रुपए बचाकर ऐसे करें पीपीएफ में निवेश, इकट्ठा हो जाएगा लाखों का फंड

पीपीएफ एक सुरक्षित और लाभदायक स्कीम है, जो आपकी छोटी बचत को बड़ा फंड बनाने में मदद करती है। यह स्कीम न केवल आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है, बल्कि भविष्य के लक्ष्यों जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की शिक्षा या घर खरीदने के लिए एक मजबूत फंड भी तैयार करती है।

5.40

आज के दौर में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना हर व्यक्ति की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए बचत और सही निवेश का चुनाव बेहद जरूरी है। अगर आप भी अपने पैसे को बिना किसी जोखिम के सुरक्षित रखना चाहते हैं और उस पर अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) स्कीम आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इस स्कीम में आप कम से कम 500 रुपए सालाना से निवेश शुरू कर सकते हैं और एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए इसमें निवेश कर सकते हैं।

पीपीएफ स्कीम क्या है?

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) एक सरकारी योजना है, जो आपको अपने पैसे को सुरक्षित रखने के साथ-साथ अच्छी ब्याज दर का लाभ भी देती है। यह स्कीम पूरी तरह से जोखिम-मुक्त है क्योंकि इसकी गारंटी खुद सरकार देती है। वर्तमान में PPF पर करीब 7.1% वार्षिक ब्याज मिलता है, जो अन्य पारंपरिक बचत योजनाओं की तुलना में अधिक है।

पीपीएफ में निवेश कैसे करें?

इस स्कीम में आप सालाना न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। अगर आप रोजाना 100 रुपए बचाते हैं, तो यह 3,000 रुपए प्रति माह और सालाना 36,000 रुपए होता है। इस राशि को आप अपने PPF खाते में जमा कर सकते हैं। 15 साल तक नियमित निवेश करने पर आप कुल लाख रुपए का निवेश करेंगे। इस निवेश पर 7.1% ब्याज के हिसाब से आपको करीब 4.36 लाख रुपए का ब्याज मिलेगा, जिससे आपका कुल फंड 9.76 लाख रुपए हो जाएगा।

पीपीएफ के लाभ

यह योजना पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि इसे सरकार समर्थित करती है। PPF में निवेश की गई राशि पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट मिलती है, और अर्जित ब्याज पर भी टैक्स नहीं लगता। यह योजना 15 साल की अवधि के लिए होती है, जिसमें आप कंपाउंडिंग के जरिए बड़ा फंड बना सकते हैं। आप अपने बजट के अनुसार इस स्कीम में निवेश राशि चुन सकते हैं।

अब फास्टटैग के डेटा पर होगी ईडी की नजर, टोल के साथ सरकार का नया प्लान

देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब टोल प्लाजा केवल शुल्क वसूली के केंद्र नहीं रहेंगे। फास्टैग और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरों से मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल वाहन चोरी रोकने, संगठित अपराध पर शिकंजा कसने और आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले संदिग्ध वाहनों की निगरानी के लिए किया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), पुलिस और अन्य अधिकृत सुरक्षा एवं जांच एजेंसियों को जरूरत के अनुसार टोल प्लाजा से जुड़े वाहन संबंधी डेटा तक नियंत्रित पहुंच दी जाएगी। किसी ब्लैकलिस्टेड या संदिग्ध वाहन के टोल प्लाजा पर पहुंचते ही संबंधित एजेंसियों को रियल-टाइम अलर्ट मिल सकेगा।

आतंकी साजिशों पर भी नजर

सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अतीत में आतंकी घटनाओं में कार, ट्रक, वैन और मोटरसाइकिल जैसे वाहनों का इस्तेमाल विस्फोटक पहुंचाने या वाहनजनित आईईडी के रूप में किया जाता रहा है। संदिग्ध वाहनों की आवाजाही का डिजिटल रिकॉर्ड मिलने से संवेदनशील इलाकों में निगरानी मजबूत होगी। किसी घटना के बाद संदिग्ध वाहन के संभावित रूट का पता लगाने में भी मदद मिलेगी।

हिट एंड रन के मामलों में खुलेगा सुराग

नई तकनीक का इस्तेमाल हिट एंड रन मामलों की जांच में भी कारगर साबित हो सकता है। दुर्घटना स्थल के आसपास मौजूद टोल प्लाजा के टाइम-स्टैम्प और वाहन ट्रैकिंग रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस संबंधित वाहन की आवाजाही का रूट तैयार कर सकेगी। इससे फरार वाहन की पहचान और उसे पकड़ने में तेजी आएगी। लूट, डकैती, अपहरण और हथियारों की तस्करी जैसे मामलों में भी यह डेटा जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण सुराग बन सकता है।

फर्जी नंबर प्लेट और क्लोन फास्टैग पर शिकंजा

देश में हर साल बड़ी संख्या में वाहन चोरी होते हैं और चोरी के वाहनों को दूसरे राज्यों या सीमावर्ती क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। अपराधी कई बार फर्जी नंबर प्लेट या क्लोन फास्टैग का इस्तेमाल कर पहचान छिपाने की कोशिश करते हैं।

अब एएनपीआर कैमरे वाहन की नंबर प्लेट पढ़ने के साथ उसके रंग, कंपनी और मॉडल जैसे विवरणों का भी मिलान करने में मदद करेंगे। यदि फास्टैग से जुड़े रिकॉर्ड और कैमरे से सामने आए वाहन के वास्तविक विवरण में अंतर पाया जाता है, तो संबंधित वाहन को संदिग्ध मानकर कार्रवाई की जा सकेगी।

डेटा की पहुंच पर रहेगा नियंत्रण

सरकार ने व्यवस्था में डेटा सुरक्षा और निजता का भी ध्यान रखा है। वाहन संबंधी जानकारी तक पहुंच केवल अधिकृत एजेंसियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत मिलेगी। एनआईए, पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय और परिवहन विभाग जैसी एजेंसियां जरूरत के अनुसार डेटा मांग सकेंगी। इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया तय की गई है और वरिष्ठ अधिकारियों के अनुरोध के आधार पर ही जानकारी साझा की जाएगी। आम लोगों के लिए यह डेटा सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

इस नई व्यवस्था से देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का टोल नेटवर्क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए एक अतिरिक्त डिजिटल निगरानी तंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा।

दक्षिण कोरिया को छोड़ उत्तर कोरिया के करीब क्यों जा रहे ट्रंप? अमेरिका के सहयोगियों की बढ़ी चिंता

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यासों को कम करने का फैसला किया है। इससे केवल लंबे समय से अमेरिका के सहयोगी रहे दक्षिण कोरिया को ठेस नहीं पहुंची है, बल्कि एशिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों में अमेरिका के सुरक्षा हितों को लेकर भी बड़ी चिंताएं पैदा हो गई हैं।

ट्रंप ने अपने फैसले की वजह बताते हुए कहा कि दक्षिण कोरिया ने ईरान के खिलाफ उनकी लड़ाई में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने अलग-थलग रहने वाले उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के साथ अपने अच्छे संबंधों का भी जिक्र किया। ट्रंप अक्सर विदेश नीति में फायदे-नुकसान और व्यक्तिगत रिश्तों को ज्यादा अहमियत देते रहे हैं। यही उनके राष्ट्रपति कार्यकाल की एक खास पहचान रही है।

जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के राष्ट्रपति कार्यकाल में यूरोपीय मामलों के सहायक विदेश मंत्री रह चुके डैन फ्राइड ने कहा, मुझे इसमें अमेरिका का कोई हित नजर नहीं आता। किसी भी स्तर पर यह समझ में नहीं आता। इससे दक्षिण कोरिया कमजोर होता है, जापान कमजोर होता है, ताइवान डरता है, नाटो चिंतित होता है और चीन को हौसला मिलता है। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया का भी हौसला बढ़ता है।

ओबामा प्रशासन में पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के सहायक विदेश मंत्री रह चुके डैनी रसेल ने कहा कि उत्तर कोरिया के पक्ष में ट्रंप का फैसला ऐसी श्रेणी में आता है, जिसमें यह समझना मुश्किल है कि इससे स्थिति और खराब कैसे हो सकती है। उत्तर कोरिया हर साल होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यासों का कड़ा विरोध करता है। उन्होंने कहा, यह दुखद रूप से पूरी तरह उलटा है। ट्रंप एक सहयोगी को सजा दे रहे हैं और एक विरोधी को बढ़ावा दे रहे हैं।

न्यूयॉर्क के एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट से जुड़े रसेल ने कहा, ट्रंप अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सुरक्षा की कीमत पर किम जोंग उन को नाराज होने से बचा रहे हैं।

रविवार को ट्रंप ने अमेरिकी सेना को 11 दिन चलने वाले 'उलची फ्रीडम शील्ड' सैन्य अभ्यास का आकार छोटा करने का आदेश दिया। यह सैन्य अभ्यास सोमवार को तय समय पर शुरू हो गया। हालांकि, यह साफ नहीं था कि अभ्यास के किन-किन हिस्सों को कम किया जाएगा।

ट्रंप के इस एलान से दक्षिण कोरिया में बहुत से लोग आश्चर्यचकित रह गए। दक्षिण कोरिया दशकों से अमेरिका का करीबी सहयोगी रहा है। वहां राष्ट्रीय सुरक्षा को बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि उसके सामने परमाणु हथियार रखने वाले उत्तर कोरिया का खतरा मौजूद है। अमेरिकी कांग्रेस (संसद) में कई डेमोक्रेट सांसदों ने भी तुरंत ट्रंप की आलोचना की। न्यूयॉर्क से डेमोक्रेट सांसद और विदेश मामलों की समिति में सबसे बड़े डेमोक्रेट नेता ग्रेग मीक्स ने एक बयान में कहा, अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक के साथ विरोधी जैसा व्यवहार करने से हमारे गठबंधन कमजोर होते हैं और चीन तथा उत्तर कोरिया को फायदा मिलता है। सोमवार को ट्रंप ने अपने फैसले का फिर समर्थन किया। उन्होंने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की फोन पर बात करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर के साथ लिखा था- हे डोनाल्ड... हम दोनों के बीच सब ठीक है, है ना?

रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही दलों के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान काम कर चुके सेवानिवृत्त अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट वुड ने कहा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तर कोरिया को रोकने के लिए बेहद अहम हैं। उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से दूरी बना रखी है और उसने हथियारों का परीक्षण भी तेज कर दिया है। वुड ने कहा, हम यह भी नहीं चाहते कि दक्षिण कोरिया यह निष्कर्ष निकाले कि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसके पास परमाणु हथियार हासिल करना ही एकमात्र गारंटी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों तरह के प्रशासन में रक्षा और खुफिया विभाग से जुड़े पदों पर रह चुके मैथ्यू क्रोनिग ने कहा कि सर्वे बताते हैं कि दक्षिण कोरियाई लोगों में अपने परमाणु हथियार विकसित करने के विचार का समर्थन लगातार बढ़ा है। क्रोनिग ने कहा, अमेरिका दक्षिण कोरिया को यह भरोसा दिलाने के लिए बहुत मेहनत करता रहा है कि वह सुरक्षित है। अब वाशिंगटन के थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से जुड़े क्रोनिग ने कहा कि सैन्य अभ्यासों का आकार कम करने से संभवतः इस भरोसे को नुकसान पहुंचता है।

ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहा दक्षिण कोरिया?

ट्रंप ने यह फैसला तब लिया, जब दक्षिण कोरिया उन्हें खुश करने और उनका समर्थन पाने की कोशिश कर रहा था। दक्षिण कोरिया व्यापार और रक्षा जैसे अहम मुद्दों पर अमेरिका का साथ चाहता था। पिछले साल नए राष्ट्रपति ली जे म्युंग जब ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहले वहां की शानदार सजावट की तारीफ की। ओवल ऑफिस को सुनहरे रंग की सजावट से सजाया गया था। ली ने ट्रंप की इस बात का भी समर्थन किया कि अगर वह 2020 में लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बन जाते, तो किम जोंग उन परमाणु हथियार बनाने की अपनी योजना को आगे नहीं बढ़ाते। ली ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में उत्तर कोरिया में ट्रंप टावर बनाया जा सकता है। इससे कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने ली के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति यून सुक योल के प्रति सहानुभूति दिखाई थी। यून को दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लगाने के बाद पद से हटा दिया गया था।

दो बंदूकें लेकर स्कूल पहुंचा छात्र, पहले टीचर पर चलाई गोली फिर साथी छात्र की हत्या कर की खुदकुशी

मनीला। दक्षिणी फिलीपींस में एक हाई स्कूल में मंगलवार को दो बंदूकें लिए एक छात्र ने अपने ही एक साथी छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद फिर खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद सैकड़ों छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

जाम्बोआंगा शहर के मेयर खाइमर अदान ओलासो ने कहा कि हमलावर ने शायद हमले की लाइव-स्ट्रीमिंग के लिए बॉडी कैमरा पहना हुआ था। यह हमला उनके शहर में एटेनिओ डी जाम्बोआंगा यूनिवर्सिटी कैंपस के हाई स्कूल में हुआ। उन्होंने बताया कि दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं।

ओलासो ने DZBB रेडियो नेटवर्क को बताया कि हमलावर ने पहले एक टीचर पर गोली चलाई, लेकिन यह साफ नहीं है कि टीचर को गोली लगी या नहीं। इसके बाद उसने अपने एक साथी छात्र को गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई, और फिर उसने खुद को गोली मार ली।

छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया

हाई स्कूल की बिल्डिंग में गोली चलने की आवाज के बाद सैकड़ों छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह बिल्डिंग एक सुरक्षित कैंपस में है, जो कैथोलिक यूनिवर्सिटी के बड़े कैंपस से अलग है। उस बड़े कैंपस में यूनिवर्सिटी के कॉलेज और प्रोफेशनल स्कूल हैं, जो जाम्बोआंगा बंदरगाह शहर में स्थित हैं।गोलीबारी के कुछ घंटों बाद पुलिस ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने छात्रों के माता-पिता और अभिभावकों से शांत रहने और बच्चों को ले जाने के लिए हाई स्कूल की सलाह और व्यवस्थाओं का पालन करने को कहा।

पुलिस ने जनता से क्या अपील की?

नेशनल पुलिस चीफ जनरल जोस मेलेंसियो नार्टिज जूनियर ने कहा, 'अधिकारी अभी घटना से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगा रहे हैं।' पुलिस सही समय पर पक्की जानकारी देगी और जनता से अपील करती है कि वे ऐसी बिना पुष्टि वाली खबरें, तस्वीरें या वीडियो शेयर न करें जिनसे बेवजह चिंता पैदा हो सकती है।' नार्टिज ने कहा, 'नेशनल पुलिस जनता को भरोसा दिलाती है कि स्कूल समुदाय की सुरक्षा और भलाई हमारी प्राथमिकता है। हम स्कूल प्रशासन, माता-पिता, अभिभावकों और समुदाय का उनके धैर्य, सहयोग और समझदारी के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अधिकारी स्थिति को संभालने का काम कर रहे हैं।' यह गोलीबारी तब हुई जब पुलिस ने भरोसा दिलाया था कि देश भर के स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इससे पहले जून में मध्य टैकलोबन शहर में हुई गोलीबारी में तीन हाई स्कूल छात्र मारे गए थे और कम से कम 20 अन्य घायल हुए थे। पुलिस ने उस गोलीबारी को अंजाम देने के आरोप में 14 और 15 साल के दो छात्रों को गिरफ्तार किया था। फिलीपींस में बंदूक के इस्तेमाल से जुड़े अपराध आम हैं, जिसका एक कारण बिना लाइसेंस वाली बंदूकों का बड़ी संख्या में होना है, लेकिन स्कूलों में गोलीबारी की घटनाएं अपेक्षाकृत कम होती हैं। फिलीपींस में यह गोलीबारी थाईलैंड में स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना के दो हफ्ते से भी कम समय के भीतर हुई। बैंकॉक के पास नोंथाबुरी प्रांत में 14 साल के एक लड़के द्वारा अपने दादा-दादी, स्कूल के पांच कर्मचारियों और 12 साल की एक लड़की की हत्या किए जाने के बाद, थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने देश में बंदूकों पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए। एशिया में बंदूक रखने के मामले में थाईलैंड का स्थान पाकिस्तान के बाद दूसरा है और यह अपने दक्षिण-पूर्वी एशियाई पड़ोसियों से कहीं आगे है।

हमास हथियार छोड़ने और गाजा की सत्ता सौंपने को तैयार, कुशनर से मिस्र में की 90 मिनट बात

हमास। हमास के नेताओं ने रविवार को मिस्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर से मुलाकात की। इस बैठक में हमास ने गाजा को हथियारों और सैन्य ढांचे से मुक्त करने की अपनी बात फिर दोहराई। यह जानकारी बैठक की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने दी। करीब 90 मिनट चली बैठक में कुशनर ने हमास से कहा कि केवल वादा करना काफी नहीं है। उसे हथियार छोड़ने की दिशा में जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने होंगे। इजराइल को भरोसा नहीं है कि हमास वास्तव में अपने हथियार छोड़ेगा। इसलिए अमेरिका चाहता है कि हमास पहले अपनी कार्रवाई से भरोसा कायम करे। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, कुशनर ने हमास नेताओं से कहा कि अगर वे सच में हथियार छोड़ते हैं तो अमेरिका भी इजराइल से उसके हिस्से के कदम उठाने की कोशिश करेगा। बैठक में हमास नेताओं ने कुशनर से कहा कि वे गाजा की शासन व्यवस्था फिलिस्तीनी तकनीकी सरकार को सौंपने के लिए तैयार हैं। यह सरकार काम शुरू करने के बाद हमास गाजा के प्रशासन में दखल नहीं देगा। अमेरिका चाहता है कि हमास गाजा के भविष्य के शासन में कोई भूमिका न रखे। इसके साथ उसे अपने सभी हथियार और सैन्य ढांचे भी खत्म करने होंगे। कुशनर ने साफ कहा कि हथियार छोड़ने के मुद्दे पर बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। उनका कहना था कि अगर हमास वास्तव में कदम उठाता है तो अमेरिका इजराइल से भी जवाबी कदम उठाने की कोशिश करेगा। ट्रंप प्रशासन और बोर्ड ऑफ पीस अमेरिका की 20 सूत्रीय शांति योजना के दूसरे चरण को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

डायरिया से डरने नहीं सतर्क रहने की जरूरत: ब्रिगेडियर डॉ. राजू अग्रवाल

डायरिया नियंत्रण व रोकथाम के लिए विशेष अभियान का शुभारम्भ

पटना। शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को डायरिया से पूरी तरह सुरक्षित बनाने और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से प्रदेश में डायरिया रोकने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है । इसी के तहत मंगलवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पटना से एम्स के अधिशाषी निदेशक (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर) प्रोफेसर ब्रिगेडियर डॉ. राजू अग्रवाल ने मिड मीडिया कैम्पेन का विधिवत शुभारम्भ किया। जागरूकता अभियान में पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू संपोषित "डायरिया से डर नहीं" कार्यक्रम के माध्यम से सहयोग प्रदान कर रहीं हैं।

इस मौके पर ब्रिगेडियर डॉ. राजू अग्रवाल, पीएसआई इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकेश कुमार शर्मा, डायरेक्टर प्रोग्राम्स हितेश साहनी व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने डायरिया से बचाव, कारण, उपचार और रोकथाम सम्बन्धी संदेशों वाले पोस्टर-बैनर और ऑडियो/वीडियो से सुसज्जित प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहन राजधानी पटना के विभिन्न क्षेत्रों में समुदाय में डायरिया के प्रति जन जागरूकता लाएंगे। इस मौके पर ब्रिगेडियर डॉ. राजू अग्रवाल ने कहा कि डायरिया से डरने नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इसका उपचार पूरी तरह संभव है। बच्चे को दिन में दो-तीन बार पतली दस्त हो तो ओआरएस का घोल और जिंक जरूर दें, क्योंकि यही इसका सही उपचार है। पीएसआई इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकेश कुमार शर्मा ने कहा कि बारिश और उमस में बच्चा डायरिया की चपेट में कई कारणों से आ सकता है, जैसे- दूषित जल पीने से, दूषित हाथों से भोजन बनाने या बच्चे को खाना खिलाने, बच्चों के मल का ठीक से निस्तारण न करने आदि से। इसलिए शौच और बच्चों का मल साफ़ करने के बाद, भोजन बनाने और खिलाने से पहले हाथों को साबुन-पानी से अच्छी तरह अवश्य धुलें।

पीएसआई इंडिया के डायरेक्टर प्रोग्राम्स हितेश साहनी ने कहा कि डायरिया के प्रति समुदाय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और ओआरएस व जिंक की महत्ता को भलीभांति समझाने के लिए ही पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य बच्चों में डायरिया की रोकथाम, ओआरएस व जिंक के उपयोग को प्रोत्साहन और जनसामान्य में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। फ्रंटलाइन वर्कर्स माताओं और परिवार वालों को यह भली भांति बताएं कि ओआरएस का घोल और जिंक बच्चे को सिर्फ डायरिया से ही नहीं बचाता बल्कि उनकी जान को भी जोखिम में जाने से बचाता है। "डायरिया से डर नहीं" कार्यक्रम के बारे में केनव्यू इंडिया के बिजनेस यूनिट हेड-सेल्फ केयर प्रशांत शिंदे का कहना है कि बच्चों को डायरिया से सुरक्षित बनाकर उन्हें सेहतमंद बनाने की हरसंभव कोशिश जारी है। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के बताये अनुसार ओआरएस सॉल्यूशन की पहुँच को बेहतर बनाना, परिवारों को इस बारे में जागरूक बनाना, फ्रंटलाइन वर्कर्स के अभिमुखीकरण और सेहत को लेकर जरूरी व्यवहार परिवर्तन को अपनाना जरूरी है। 'डायरिया से डर नहीं' पहल के जरिए, केनव्यू पीएसआई इंडिया के साथ मिलकर सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं में अहम योगदान दे रहा है। इससे बच्चों की देखभाल करने वाले न सिर्फ़ ओआरएस और जिंक की अहमियत को समझ रहे हैं, बल्कि डायरिया होने पर तुरंत इसे अपनाने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। हम बच्चों की रोकी जा सकने वाली बीमारियों और मौतों को कम करने की सरकार की कोशिशों में अपना सहयोग जारी रखने का वादा करते हैं। इसके लिए जागरूकता को प्राथमिकता देने के साथ ही कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाएँगे और जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ जीवन बचाने वाले उपायों तक पहुँच बेहतर बनाएंगे। इस मौके पर बिहार पीएसआई इंडिया राज्य प्रतिनिधि सौरव तिवारी, सीनियर मैनेजर प्रोग्राम अनिल द्विवेदी एवं पीएसआई इंडिया टीम से लोग उपस्थित रहे।

पोस्टर प्रतियोगिता के जरिए बच्चों को डायरिया के प्रति किया जागरूक

दरभंगा। डायरिया के प्रति जागरूकता की अलख जगाने के उद्देश्य से जिले के स्कूलों में विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं 1 इसी क्रम में मंगलवार को मध्य विद्यालय,उखड़ा, हनुमान नगर में पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गयी 1 स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू के सहयोग से "डायरिया से डर नहीं" कार्यक्रम के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता में कक्षा-छह, सात और आठ के 20 विद्यार्थियों ने भाग लिया 1 प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आनंद कुमार- वर्ग – आठ, द्वितीय स्थान राफिया नाज-वर्ग – सात, और तृतीय स्थान मनतसा नाज-वर्ग –आठ ने प्राप्त किया 1

प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर शिक्षकों और विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल रहा और उन्होंने पूरी तन्मयता से कार्यक्रम में भाग लेने के साथ ही इस मौके पर डायरिया से जुड़ी जो जरूरी जानकारी उन्हें मिली उसे वह घर जाकर अपने भाइयों-बहनों और परिजनों से भी साझा करने का संकल्प लिया 1 प्रतियोगिता के आयोजन में विद्यालय के प्रधानाध्यापक पुरुषोतम कुमार जायसवाल का सराहनीय सहयोग रहा

1 इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से बहुत ही सहज और सरल तरीके से बच्चों के बीच डायरिया के संभावित कारणों एवं बचाव की समझ विकसित करने की कोशिश की गयी, जो कि बच्चों को डायरिया से सुरक्षित बनाने में बहुत ही मददगार साबित मिलेगी 1 उन्होंने कहा कि अभी बरसात के मौसम में संक्रामक बीमारियों से बचाव का सबसे सरल और कारगर तरीका साबुन और पानी से हाथों को अच्छी तरह से धुलना है। खाना खाने से पूर्व, खाना खाने के बाद, खाना बनाने से पहले, शौच के बाद एवं घर के साफ सफ़ाई के बाद हाथों को साबुन-पानी से अच्छी तरह धुलते हैं तो हाथ स्वच्छ एवं कीटाणु मुक्त होगा और बीमारियां दूर रहेंगी। पीएसआई इंडिया के संजय तरुण ने बताया कि हाथ धोने के विभिन्न चरणों का पालन कर बच्चों को डायरिया समेत कई अन्य संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित बनाया जा सकता है। बच्चे को दस्त की शिकायत हो तो तुरन्त ओआरएस का घोल एवं जिंक देना शुरू करना चाहिए जो कि स्थानीय सरकारी अस्पतालों एवं आशा, एएनएम दीदी के पास निःशुल्क उपलब्ध है। इसी क्रम में गत दिनों स्थानीय मध्य विद्यालय खाजा सराय, स्वर्णलता मध्य विद्यालय, खरगा खाजासराय में भी क्विज एवं पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं । प्रतियोगिता में इन दोनों विद्यालयों के कक्षा-छह, सात और आठ के 20-20 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक और एवं शिक्षकों के साथ पीएसआई इंडिया के अखिलेश कुमार ने भाग लिया। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तीन-तीन विद्यार्थियों को प्रधानाचार्य के द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया 1 मध्य विद्यालय खाजासराय में प्रथम स्थान पर लक्ष्मी कुमारी-वर्ग –सात, द्वितीय स्थान पर रिया कुमारी वर्ग-आठ और तृतीय स्थान रहीं सोनाली कुमारी-वर्ग-सात रहीं । दूसरी ओर स्वर्णलता मध्य विद्यालय ,खरगा खाजा सराय में प्रथम स्थान पर संस्कृति कुमारी-वर्ग –सात, द्वितीय स्थान पर साबिया नूर-वर्ग – आठ और तृतीय स्थान पर छोटी कुमारी-वर्ग –आठ रहीं।

हेमा मालिनी ने देखी 'बंटवारा 1947'; बोलीं- 'सनी देओल की एक्टिंग जबर्दस्त', पोते करण की तारीफ में कही ये बात

फिल्म 'बंटवारा 1947' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। भारत और पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी और करण देओल अहम भूमिकाओं में हैं। दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी ने हाल ही में यह फिल्म देखी और अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्हें यह फिल्म पसंद आई है।

हेमा मालिनी को पसंद आया सनी का अभिनय

हेमा मालिनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने फिल्म की तारीफ की है। साथ ही सनी देओल और शबाना आजमी के अभिनय को जबर्दस्त बताया है। साथ ही पोते करण देओल के अभिनय पर भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है। इस फिल्म को बनाने के लिए ड्रीम गर्ल ने आमिर खान को बधाई दी है। फिल्म का संदेश उन्हें काफी प्रेरित करने वाला लगा।

हेमा मालिनी ने क्या लिखा है?

हेमा मालिनी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, 'मैंने कल फिल्म 'बंटवारा' देखी। यह सच में बेहद शानदार है और एक साफ संदेश देती है कि आज देश को किस चीज की जरूरत है?

हेमा मालिनी ने आगे लिखा है, यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि नफरत और बंटवारे से कहीं ज्यादा जरूरी इंसानियत, आपसी सम्मान और भाईचारा है।

मुझे उम्मीद है कि फिल्म का खूबसूरत संदेश लोगों को अपनी सोच बदलने और नफरत के बजाय करुणा व दया चुनने के लिए प्रेरित करेगा।

राजकुमार संतोषी का निर्देशन शानदार है और सनी देओल व शबाना आजमी की एक्टिंग भी जबर्दस्त रही।

करण देओल और प्रीति जिंटा ने भी अच्छा काम किया है।

आमिर खान को ऐसी सदाबहार फिल्म बनाने के लिए बहुत बधाई। इस फिल्म का मैसेज सच में आज की जरूरत है।

धर्मेंद्र ने जब देखी थी 'बंटवारा 1947', भर आई थीं आंखें

फिल्म 'बंटवारा 1947' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में इस फिल्म के निर्देशन राजकुमार संतोषी ने सनी देओल के पिता व दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र का जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि यही ('बंटवारा 1947') आखिरी फिल्म थी, जो धर्मेंद्र ने देखी थी। संतोषी ने कहा, 'यह फिल्म धर्मेंद्र ने भी देखी थी और देखकर काफी भावुक हो गए थे। धरम जी का आशीर्वाद बहुत है फिल्म के लिए। नैरेशन जब सुना था तो वे बहुत इमोशनल थे। आंख में आंसू आ गये थे और बहुत आशीर्वाद दिया। धरम जी की मेरे ख्याल से यह आखिरी फिल्म है, जो उन्होंने देखी थी। तब भी उन्होंने बोला 'राज ये पिक्चर बहुत चलेगी। बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने'।

देओल परिवार के बारे में

बता दें कि दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी। उनके साथ चार बच्चे-सनी देओल, बॉबी देओल व बेटियां- विजेता और अजीता हैं। धर्मेंद्र का दूसरा विवाह हेमा मालिनी से हुआ। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की दो बेटियां- एशा देओल और अहाना देओल हैं।

'पुराने अच्छे दिन...', आलिया भट्ट ने साझा की रणबीर-राहा के साथ वेकेशन फोटोज; फैंस को भी भाया अंदाज

आलिया भट्ट जब फिल्मों में व्यस्त नहीं रहती हैं तो पति और अभिनेता रणबीर कपूर के साथ वेकेशन पर निकल जाती हैं। ऐसी ही एक पुरानी वेकेशन की तस्वीरें आलिया ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम पेज पर साझा की हैं।

आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें साझा कीं, इन तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा, 'पुराने अच्छे दिन। गले लगना और भी बहुत कुछ।' इन तस्वीरों में वह अपनी बेटी राहा के गले लगी हुई नजर आ रही हैं। रणबीर कपूर और राहा के साथ वेकेशन का खूब आनंद ले रही हैं।

आलिया भट्ट ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें वह पति रणबीर और बेटी राहा के साथ एक बोट पर बैठी हैं। समंदर की सैर पर यह परिवार निकला है।

बेटी राहा के साथ गुजरा वक्त

आगे कुछ तस्वीरों में आलिया अपनी बेटी राहा के साथ वक्त गुजार रही हैं। बेटी राहा ने भी आलिया को गले लगाया हुआ है। यह पल आलिया के लिए कभी न भूलने वाले हैं।

वेकेशन पर डाइटिंग भूल गईं आलिया

अभिनेत्री होने के नाते आलिया अपनी फिटनेस, फिगर पर ध्यान देती हैं लेकिन वेकेशन पर वह डाइटिंग को भूल गई हैं। मनपसंद खाना खा रही हैं। अपनी सेल्फी भी वह क्लिक कर रही हैं।

आलिया भट्ट करियर फ्रंट पर क्या रही हैं?

हाल ही में आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' रिलीज हुई। इसके अलावा वह संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' कर रही हैं। इस फिल्म में रणबीर कपूर और विक्की कौशल भी हैं।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित । शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com